@saahassamachar @saahassamachar @saahassamachar

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

राष्ट्रीय संस्करण

साहस समाचार

निष्पक्ष, निर्भीक, बेबाक

नेहा धूपिया ने अपनी मां के लिए...पेज-8

नई दिल्ली, सोमवार, 28 सितंबर 2026, वर्ष-1, अंक-298, पृष्ठ-8, मूल्य-2 रुपए RNI No-DLHIN/25/A2841 www.saahassamachar.in

पिछली सरकार ने 12 लाख करोड़ के घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया: शाह

अहमदाबाद, एजेंसी।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील सरकार (संप्रग) सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने 12 लाख करोड़ के घपले-घोटालों के अलावा कुछ नहीं किया, जबकि मोदी सरकार पर 12 वर्षों में चार आने के भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। शाह ने गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती रेलवे स्टेशन से 1472 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और देश की पहली एलएनजी ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इसके साथ ही उन्होंने रेलवे लोको इंजन के रखरखाव के लिए शुरू किए जा रहे डब्ल्यूएजी-12 मेंटेनेंस शेड का भी उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए उन्हें आंकड़ों के साथ चर्चा करने की नसीहत दी और कहा कि संप्रग के 10 वर्षों के शासन के दौरान 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के अलावा विपक्षी पार्टी ने कुछ नहीं किया। वहीं मोदी सरकार पर 12 वर्षों में चार आने के भी भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा पाया। उन्होंने कहा कि आज साबरमती मंडल में रेलवे की कई परियोजनाएं शुरू हुई हैं, जो पर्यावरण, जन सुविधा और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ी हैं।

सत्याग्रह, सादा जीवन, ग्रामीण विकास और खादी जैसे सभी प्रयोगों को जमीन पर उतारने की शुरुआत साबरमती से ही हुई। उन्होंने कहा कि साबरमती रेलवे स्टेशन अब काफी विकसित हो चुका है। उन्होंने कहा कि 1980 के दशक में यहाँ से रिक्शा लेने के लिए भी दो किलोमीटर चल कर जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और सम्पर्क की दृष्टि से साबरमती रेलवे स्टेशन में आमूलचूल बदलाव हुए हैं।

शाह ने कहा कि आज 1472 करोड़ रुपये की लागत वाली जिन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, वह आने वाले दिनों इस क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने कहा कि 700 करोड़ रुपये की लागत से यहाँ रेलवे लोको इंजन के रखरखाव के लिए डब्ल्यूएजी-12 मेंटेनेंस शेड बनाया गया। वहीं, 48 करोड़ रुपये की लागत से सुरक्षा के लिए साबरमती-कलोल-साबरमती रेलखंड पर 'कवच' प्रणाली की शुरुआत की गयी। साथ ही, अहमदाबाद-पालनपुर रेल खंड और अहमदाबाद-सामाख्याली रेल खंड पर 'कवच', साबरमती-सरखेज रेल मार्ग का दोहरीकरण जैसे कार्य शुरू हुए हैं।

केंद्रीय गृहमंत्री कहा कि आज 12,000 हॉर्सपावर की ट्विन-सेक्शन क्षमता वाले एक ऐसे इंजन की शुरुआत हुई है, जो अकेले ही लगभग 600 ट्रकों जितना माल खींच सकती है। पहले दो लोकोमोटिव लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही डब्ल्यूएजी-12 यह काम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह देश को भारतीय रेलवे के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पड़ाव पर पहुँचाएगा। श्री शाह ने कहा कि आज जिस एलएनजी से चलने वाली ट्रेन की शुरुआत हुई है, वह आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देगी।

श्री शाह ने कहा कि 2014 में श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद रेलवे में कई नयी सुविधाएँ आईं और इसे आधुनिक बनाया गया। उन्होंने कहा कि मुंबई स्थित जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) से वडोदरा तक पहली डबल-स्टैक लॉन्ग-हॉल कंटेनर ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा हो चुका है।

आतंकवाद से समझौता नहीं, आत्मरक्षा का अधिकार कायम: जयशंकर

नई दिल्ली, एजेंसी।

भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में आतंकवाद के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की अपनी नीति को दृढ़ता से दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को सामान्य घटनाएं बनाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती और भारत अपने आत्मरक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करेगा। विदेश मंत्री जयशंकर ने शनिवार रात संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81 में सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है और वैश्विक संस्थाओं में व्यापक भागीदारी के लिए सुधार आधारित बहुपक्षवाद की जरूरत लगातार मजबूत हो रही है।

उन्होंने कहा कि आतंकवाद को समर्थन देने वाली सरकारों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और आतंकवाद के वित्तीय स्रोतों को उजागर कर उन पर रोक लगनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आतंकवाद और मित्रता साथ-साथ नहीं चल सकते तथा आतंकवाद के आधार पर बनी समझ को स्वाभाविक रूप से चुनौती दी जाएगी। विदेश मंत्री ने दुनिया के अनेक हिस्सों में जारी संघर्षों पर चिंता जताते हुए खाड़ी में जारी संघर्ष को लेकर तनाव कम करने, नागरिकों की सुरक्षा तथा ऊर्जा और व्यापार के निर्बाध प्रवाह की अपील की। यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में भारत ने कहा कि अंतहीन युद्ध अब खत्म होना चाहिए और शांति की दिशा में जारी प्रयासों का समर्थन किया। पश्चिम एशिया में भारत ने स्थायी शांति के लिए दो-राष्ट्र समाधान को जरूरी बताया और फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता जारी रखने की बात कही। भारत ने कहा कि शांति केवल युद्ध की अनुपस्थिति नहीं है।

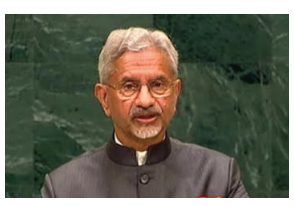

वांगचुक ने कॉजपा के प्रदर्शन को समर्थन दिया

नई दिल्ली,एजेंसी। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 'कॉकरोच जनता पार्टी' (कॉजपा) के दो अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन का समर्थन किया और कहा कि देश में जवाबदेही तथा चुनावी प्रक्रिया में सुधार के प्रयासों का समर्थन किया जाना चाहिए। कॉजपा के प्रस्तावित आंदोलन को समर्थन देते हुए वांगचुक ने कहा कि वह प्रदर्शन के दौरान संभवतः व्यक्तिगत रूप से मौजूद नहीं रहेंगे। वांगचुक ने कहा, समर्थन निश्चित रूप से है। देश में जवाबदेही बेहतर करने के लिए जो भी प्रयास होंगे, मैं हमेशा उनके साथ हूं। उन्होंने कहा, मेरे लिए आंदोलनों का समर्थन करने का मकसद यही है कि ये आंदोलन अपने दम पर आगे बढ़ें। अब इस मुद्दे को लेकर कई लोग सामने आ गए हैं और यह देखकर मुझे खुशी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त से जुड़े इस मुद्दे पर मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी।

आतंकवाद का कड़ा और निर्णायक जवाब देंगे: मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, सर्जिकल स्ट्राइक ने आतंकवाद से निपटने की भारत की नीति का नया उदाहरण पेश किया

नई दिल्ली, एजेंसी।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि 2016 में की गई 'सर्जिकल स्ट्राइक' आतंकवादी हमलों का दर्द झेल रहे भारत का निर्णायक जवाब थी और इसने आतंकवाद से निपटने की देश की नीति का एक नया उदाहरण दुनिया के सामने पेश किया। मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चलता है और देश ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद का कड़ा एवं निर्णायक जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में बालाकोट हवाई हमले से लेकर 'ऑपरेशन सिंदूर' तक भारत ने कई बार यह स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी देश पर बुरी नजर डालने का दुस्साहस करेंगे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने 2016 की 'सर्जिकल स्ट्राइक' का जिक्र करते हुए कहा कि भारत के वीर जवानों ने जिस तरह नियंत्रण रेखा (एलओसी) पार कर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की, उससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। मोदी ने कहा, भारत की एक बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि की 10वीं वर्षगांठ बस एक दिन बाद है और वह उपलब्धि 'सर्जिकल स्ट्राइक' है। भारतीय सेना ने 10 साल पहले 28-29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकवादी हमलों का दर्द लंबे समय तक सहा और 'सर्जिकल स्ट्राइक' इसका निर्णायक जवाब थी।

उन्होंने कहा,'सर्जिकल स्ट्राइक' ने आतंकवाद से निपटने की भारत की नीति का एक नया उदाहरण पूरी दुनिया के सामने साहसिक तरीके से पेश किया।

भारतीय बलों ने जम्मू-कश्मीर के उरी में सेना के एक शिविर पर आतंकवादी हमले के बाद नियंत्रण रेखा के पार आतंकवादी शिविरों पर 'सर्जिकल स्ट्राइक' की थी। उरी हमले में 18 जवान शहीद हुए थे। मोदी ने कहा कि भारत लंबे समय से आतंकवादी हमलों के जख्म झेलता रहा है और एक समय ऐसा था जब देश में सिलसिलेवार बम धमाके आम बात हो गए थे। उन्होंने कहा कि 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में हुए सिलसिलेवार धमाकों में कई निर्दोष लोगों की जान चली गई थी।

प्रधानमंत्री ने कहा, इसके कुछ ही सप्ताह बाद मुंबई में 26/11 (26 नवंबर 2008) का भीषण हमला हुआ। पहले भी हर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठती थी लेकिन इन मांगों पर अक्सर उचित ध्यान नहीं दिया जाता था और बस समय बीतने का इंतजार किया जाता था। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति पर चल रहा है और इसके परिणाम सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन दिए जाने का उल्लेख ऐसे समय किया है जब दो दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान कश्मीर मुद्दा उठाया था। शरीफ ने कश्मीर मुद्दा उठाते हुए कहा था कि दक्षिण एशिया को 2025 जैसे संघर्ष के मुहाने पर दोबारा पहुंचने से रोकने के लिए कश्मीर मुद्दे का न्यायसंगत समाधान जरूरी है। भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र के अन्य मंचों पर कश्मीर को लेकर उठाए जाने वाले पाकिस्तान के दावों को लगातार खारिज करता रहा है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर उसका अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। भारत ने 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 आम लोगों की मौत के जवाब में पिछले साल सात मई को 'ऑपरेशन सिंदूर' शुरू किया था और पाकिस्तान एवं पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढांचों को निशाना बनाया था।

स्वच्छता ही बापू को दी जाने वाली सबसे सुंदर श्रद्धांजलि:प्रधानमंत्री

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 138वें एपिसोड में देशभर में चल रहे स्वच्छता अभियानों की सराहना की। उन्होंने कहा कि युवाओं और समुदायों द्वारा किए जा रहे ये प्रयास महात्मा गांधी के स्वच्छता पर दिए गए जोर के अनुरूप हैं। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती आने वाली है। इस मौके को याद करते हुए पीएम मोदी ने स्वच्छता पर बापू के संदेश को दोहराया और लोगों से अपने आसपास सफाई बनाए रखने में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की।

पीएम मोदी ने कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, 2 अक्टूबर बस कुछ ही दिन दूर है। यह हमारे पूज्य बापू की जयंती है। बापू ने हमें जीवन के कई मंत्र दिए। स्वच्छता उनमें से एक है। हम अक्सर अपने आसपास स्वच्छता से जुड़े कई प्रयास देखते हैं। ये प्रयास बहुत प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक हैं। सोशल मीडिया पर भी ऐसी तस्वीरें, वीडियो और रील्स बार-बार हमारा ध्यान खींचती हैं। हाल के दिनों में मैंने ऐसे कई प्रयास देखे हैं। सामूहिक भागीदारी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की पहल पूरे समुदाय को प्रेरित कर सकती है। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने इसकी शुरुआत की और लोग जुड़ते गए। इसे ही जनभागीदारी कहते हैं। स्वच्छता ही सबसे सुंदर श्रद्धांजलि है जो हम बापू को दे सकते हैं।

सार समाचार

असम में रांका सहित सीजेपी कार्यकर्ता हिरासत में

गुवाहाटी,एजेंसी। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दिपके ने रविवार को कहा कि असम में आशुतोष रांका और सीजेपी की एक टीम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। दिपके ने बताया कि उनती टीम राज्य में सीजेपी कार्यकर्ताओं की एक बैठक में शामिल होने पहुंची थी। उन्होंने कहा कि असम पुलिस ने आशुतोष रांका को एक निजी आवास से हिरासत में लिया और बाद में उन्हें तथा उनके साथियों को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। हिरासत के कारणों या उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की तत्काल जानकारी नहीं मिल सकी है। दिपके ने कहा कि श्री रांका और अन्य लोगों की कानूनी सहायता के लिए वकील उस स्थान के बाहर मौजूद हैं, जहां उन्हें कथित तौर पर रखा गया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं दी है।

केरल में भाजयुमो कार्यकर्ता ने दिखाये प्रियंका गांधी को काले झंडे

कोझिकोड,एजेंसी। कांग्रेस महासचिव एवं वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के काफिले को भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के कार्यकर्ताओं ने रविवार को केरल के कोझिकोड में काले झंडे दिखाये। पुलिस ने बताया कि श्रीमती वाड्रा का काफिला जब तिरुवंबाडी के पास थम्बलमन्ना से गुजर रहा था, तब कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारे भी लगाये। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाया और बाद में मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। काफिला बिना रुके आगे बढ़ गया।

अरुणाचल प्रदेश बाल तस्करी मामले में 51 लोग बचाए गए

ईटानगर,एजेंसी। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में पुलिस ने बाल तस्करी गिरोह से जुड़े मामले में 47 बच्चों समेत 51 लोगों को तलाश कर बचाया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। नामसाई थाने में दर्ज मामले में कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले परिवारों के बच्चों की अवैध खरीद-फरोख्त, उनकी तस्करी करने और उन्हें अन्य लोगों के पास रखने के आरोप हैं। नामसाई के पुलिस अधीक्षक सांगे थिनले ने बताया कि लगातार जांच, मैदानी स्तर पर सत्यापन और कई जिलों तथा राज्यों में चलाए गए समन्वित अभियानों के कारण बचाए गए बच्चों की संख्या शुरुआती चरण में 19 से बढ़कर पहले 38 और अब 51 हो गई है।

यूपीआई भुगतान पर एमडीआर के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम सुनवाई

नई दिल्ली,एजेंसी।

उच्चतम न्यायालय 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर यानी व्यापारी से लिया जाने वाला शुल्क) लगाने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। यूपीआई भुगतान लगभग छह वर्ष तक पूरी तरह निःशुल्क था। सरकार ने 15 अक्टूबर से यूपीआई मंच के जरिये व्यापारियों को 2,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लगाने का फैसला किया है।

हालांकि, व्यक्ति से व्यक्ति के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेनदेन और छोटी राशि के भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके माध्यम से 75,000 रुपये या उससे अधिक के भुगतान पर एमडीआर की अधिकतम सीमा 300 रुपये होगी।

रेलवे, दूरसंचार, बीमा, ईंधन और कृषि संबंधी सामग्री जैसे आवश्यक सेवाओं तथा कम लाभ वाले क्षेत्रों में 2,000 रुपये से अधिक के प्रत्येक लेनदेन पर पांच रुपये का निश्चित एमडीआर लगेगा। म्यूचुअल फंड, प्रतिभूतियों तथा शेयर ब्रोकर एवं डीलरों के माध्यम से किए जाने वाले भुगतान पर 0.02 प्रतिशत एमडीआर लगेगा और इसकी अधिकतम सीमा भी 300 रुपये होगी। व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। भले ही राशि कितनी भी हो। पी2पी लेनदेन यूपीआई के कुल लेनदेन की संख्या का 37 प्रतिशत और कुल लेनदेन मूल्य का 70 प्रतिशत हैं। उच्चतम न्यायालय की 28 सितंबर की वाद सूची के अनुसार, अधिवक्ता अंजन दत्ता की याचिका पर प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ सुनवाई करेगी। दत्ता की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र की 14 सितंबर की अधिसूचना और 15 सितंबर को घोषित उस एमडीआर व्यवस्था को चुनौती दी गई है, जो 15 अक्टूबर से प्रभावी होनी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि पर्याप्त वैधानिक सुरक्षा उपायों, पारदर्शिता और सार्वजनिक परामर्श के बिना यह शुल्क लगाया गया है। याचिका में भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की संशोधित धारा 10ए की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी गई है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और कई अन्य सरकारी बैंक रविवार को खुले रहे

सरकारी बैंक कर्मचारियों की आज से तीन दिनों की हड़ताल

नई दिल्ली, एजेंसी।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई), बैंक ऑफ बड़ौदा (बीओबी), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और कई अन्य सरकारी बैंक रविवार को खुले हैं। इससे आम जनता को 28 सितंबर से 30 सितंबर तक होने वाली प्रस्तावित तीन-दिनों की देशव्यापी बैंक हड़ताल से पहले अपने बैंकिंग काम पूरे करने का मौका मिल रहा है। रविवार को बैंक खोलने का यह खास फैसला सरकारी बैंकों (पीएसबी) और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आआरबी) पर लागू होता है। यह कदम प्रस्तावित हड़ताल से पहले रेगुलर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के मकसद से उठाया गया है। रविवार को पीएसबी और आरआरबी

खोलने का फैसला 21 सितंबर को वित्त मंत्रालय, पब्लिक सेक्टर बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (आईबीए) और नाबार्ड के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद लिया गया।

यह कदम इसलिए भी अहम है क्योंकि 26 और 27 सितंबर को क्रमशः शनिवार और रविवार पड़ रहे हैं। वीकेंड के ठीक बाद प्रस्तावित बैंक हड़ताल के कारण, ग्राहकों को कई दिनों तक बैंक की ब्रांच से जुड़ी सेवाओं का सीमित लाभ मिल पाता। इसलिए, हड़ताल से पहले जरूरी बैंकिंग लेन-देन पूरे करने का एक अतिरिक्त मौका देने के लिए रविवार को बैंक खोलने की योजना बनाई गई है। आज काम कर रहे पब्लिक सेक्टर बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक शामिल हैं।

इस व्यवस्था में देश भर के 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी शामिल हैं। इनमें आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, असम ग्रामीण बैंक, बिहार ग्रामीण बैंक, छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक, गुजरात ग्रामीण बैंक, हरियाणा ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक, झारखंड ग्रामीण बैंक, कर्नाटक ग्रामीण बैंक, केरल ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, मणिपुर ग्रामीण बैंक, मेघालय ग्रामीण बैंक, मिजोरम ग्रामीण बैंक, नागालैंड ग्रामीण बैंक, ओडिशा ग्रामीण बैंक, पुडुचेरी ग्रामीण बैंक, पंजाब ग्रामीण बैंक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक और पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक शामिल हैं। हालांकि, रविवार को बैंक खोलने की यह व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर के बैंकों पर अपने आप लागू नहीं होती है।

शांति भारत की नीति, कमजोरी नहीं : राजनाथ

नई दिल्ली, एजेंसी।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत शांति में विश्वास करता है और किसी देश की जमीन पर कब्जा नहीं चाहता, लेकिन शांति को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक स्थिरता चाहता है, पर अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की कीमत पर नहीं। खतरा होने पर देश अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने को प्रतिबद्ध है। सिंह ने रविवार को यहां एक सम्मेलन में कहा कि भारत के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती।

आतंकवाद को सरकारी नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने या आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को स्पष्ट संदेश दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश की आतंकवाद समर्थक नीति जारी रहने तक भारत को इसके खिलाफ सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार है। सिंह ने राष्ट्रीय एकता को राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम आधार बताते हुए धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र के आधार पर विभाजन से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने भारत के दृष्टिकोण के आधार 'वसुधैव कुटुंबकम' और 'सबका साथ, सबका विकास' सहित सम्मान, संवाद, समृद्धि, सुरक्षा और संस्कृति को पांच रणनीतिक स्तंभ बताये।

उन्होंने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ के लिए भरोसेमंद साझेदार और 'विश्व बंधु' के रूप में उभर रहा है।

विश्व पर्यटन दिवस पर दौड़ी दिल्ली, 1,500 से अधिक धावकों ने लिया हिस्सा

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां, फिटनेस प्रेमी और विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी मौजूद रहे।

नई दिल्ली,एजेंसी।

विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित गांधी दर्शन, राजघाट में 17वीं चैम्पियंस रन का आयोजन किया गया। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति तथा हेल्थ फिटनेस ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस दौड़ में 1,500 से अधिक धावकों ने 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। आयोजन में फिटनेस के साथ भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। दौड़ को पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारी, खेल जगत से जुड़ी हस्तियां, फिटनेस प्रेमी और विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागी मौजूद रहे। एशियाई मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा और समिति के निदेशक डॉ. संजीत कुमार भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। 'फिट इंडिया-अतुल्य भारत' की भावना के साथ आयोजित चैम्पियंस रन में 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की दौड़ के अलावा 1 किलोमीटर की फिटनेस एवं पारिवारिक दौड़ आयोजित की गई। गांधी दर्शन परिसर में सुबह से ही धावकों और उनके साथ पहुंचे लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

आयोजन के माध्यम से लोगों को नियमित व्यायाम और सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया गया। आयोजकों ने कहा कि स्वस्थ जीवनशैली के साथ देश की ऐतिहासिक विरासत और पर्यटन स्थलों को जानने-समझने की संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विजय गोयल ने कहा कि स्वस्थ भारत ही एक सशक्त और आत्मविश्वासी भारत की नींव है। उन्होंने कहा कि चैम्पियंस रन जैसे आयोजन फिटनेस के संदेश को केवल विचार तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे जनभागीदारी से जोड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि जब बड़ी संख्या में लोग एक साथ दौड़ते हैं और व्यायाम को जीवन का हिस्सा बनाने का संकल्प लेते हैं, तो इससे विशेष रूप से युवाओं को प्रेरणा मिलती है। उन्होंने युवाओं से शारीरिक गतिविधियों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। विजय गोयल ने कहा कि भारत केवल ऐतिहासिक स्मारकों, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए ही नहीं जाना जाता, बल्कि यहां खेल और ऊर्जा की भी समृद्ध परंपरा है। उन्होंने 'खेलो इंडिया, खिलोगे इंडिया' की भावना का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों और युवाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने से उनमें अनुशासन, सहभागिता और आत्मविश्वास की भावना विकसित होती है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यटन को देश की विविध विरासत और पर्यटन स्थलों से लोगों को जोड़ने के महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत आने वाले पर्यटक यहां के ऐतिहासिक स्मारकों, आध्यात्मिक केंद्रों, सांस्कृतिक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य के माध्यम से देश की विविधता को करीब से अनुभव करते हैं। चैम्पियंस रन की प्रमुख प्रेरक शक्ति और एशियाई मैराथन चैंपियन डॉ. सुनीता गोदारा ने कहा कि 17वें संस्करण में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी उत्साहजनक है। उन्होंने कहा कि पिछले 16 वर्षों से आयोजन का उद्देश्य फिटनेस के संदेश को प्रतिस्पर्धात्मक खेलों से आगे ले जाकर दौड़ को सभी के लिए उत्सव का रूप देना रहा है।

दिल्ली विस लोकतांत्रिक आवाज और स्वतंत्रता संग्राम की जीवंत गाथा: मोहन सिंह बिष्ट

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने रविवार को कहा कि दिल्ली विधानसभा उन महान व्यक्तित्वों के साहस की जीवंत गवाही है, जिन्होंने भारत की लोकतांत्रिक आवाज को सशक्त किया और स्वतंत्रता संग्राम को नया आयाम दिया। मोहन सिंह बिष्ट ने आज वीर विठ्ठलभाई झावरभाई पटेल की 153वीं जयंती और शहीद भगत सिंह की 119वीं जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करते हुए यह बात कही। दिल्ली विधानसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी दोनों महान विभूतियों को पुष्पांजलि अर्पित की।

इस मौके पर विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि वीर विठ्ठलभाई पटेल और शहीद भगत सिंह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दो सशक्त आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक ने विधाई संस्थाओं के माध्यम से भारतीयों की आवाज और गरिमा को सशक्त किया, जबकि दूसरे ने अपने साहस और बलिदान से पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया। ऐतिहासिक दिल्ली विधानसभा परिसर हमें याद दिलाता है कि भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष विधाई संस्थाओं के भीतर भी लड़ा गया और उनके बाहर भी। उन्होंने वीर विठ्ठलभाई पटेल के ऐतिहासिक योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि 24 अगस्त 1925 को वे केंद्रीय विधानसभा के प्रथम भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष (स्पीकर) बने थे। उस समय केंद्रीय विधानसभा का संचालन वर्तमान दिल्ली विधानसभा परिसर से ही होता था।

उनका कार्यकाल भारत के संसदीय इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव था। विठ्ठलभाई पटेल ने आसंदी की स्वतंत्रता और गरिमा को बनाए रखा, सदस्यों के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा की तथा एक स्वतंत्र विधान सभा सचिवालय की स्थापना की दिशा में कार्य किया। निष्पक्षता, संसदीय अनुशासन और संस्थागत स्वायत्तता की उनकी विरासत आज भी देश की विधाई संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। शहीद भगत सिंह को स्मरण करते हुए मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि उनका नाम ऐतिहासिक केंद्रीय विधानसभा से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है।

जहां 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने औपनिवेशिक कानूनों के विरोध में बम फेंके और उसके बाद हुई कार्यवाही के माध्यम से अपने प्रतिरोध का संदेश देश तक पहुंचाया। भगत सिंह का साहस, देशभक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने का उनका संकल्प आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।

पीएम-उदय योजना: नियमितीकरण शुल्क में 75% की अतिरिक्त छूट

31 अक्तूबर तक मिलेगा लाभ,स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने प्रस्ताव को दी मंजूरी।

नई दिल्ली,एजेंसी।

पीएम-उदय योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में बने मकानों के निर्मित क्षेत्र को नियमित कराना अब सस्ता हो गया है। एमसीडी की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने नियमितीकरण शुल्क में 75 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह लाभ 31 अक्तूबर तक नियमितीकरण कराने वाले आवेदकों को मिलेगा। सत्या शर्मा ने बताया कि योजना के तहत नियमितीकरण के लिए लिए जाने वाले चार शुल्कों-कम्पन्सेटरी रेगुलेटरी चार्ज, सीएंडडी चार्ज, डेवलपमेंट चार्ज और एडमिन/आईटी चार्ज पर 75 प्रतिशत तक की अतिरिक्त राहत दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य अनधिकृत कॉलोनियों में लंबे समय से रह रहे लोगों को उनकी संपत्तियों का अधिकार दिलाना है। शुल्क में छूट से लोगों को अपने मकानों का निर्माण नियमानुसार दर्ज कराने में सुविधा होगी। एमसीडी पहले ही यूबीबीएल-2016 के तहत लगने वाले कई शुल्क समाप्त कर चुकी है।

इनमें परमिट फीस, बेटरमेंट चार्ज, लेवी, अतिरिक्त लेवी, प्लिंथ फीस, प्री-ऑक्यूपेंसी चार्ज और बिना स्वीकृति निर्माण से संबंधित शुल्क शामिल हैं। श्रम उपकर भी नियमितीकरण शुल्क में शामिल नहीं है। नियमितीकरण प्रक्रिया आसान बनाने के लिए 27 जुलाई से सूचीबद्ध पेशेवरों के माध्यम से सेल्फ असेसमेंट के आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने की व्यवस्था लागू की गई है। जागरूकता के लिए शिविर, एसएमएस और प्रचार अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दिल्ली की 1,511 अनधिकृत कॉलोनियां पीएम-उदय कानून के दायरे में हैं। इनमें करीब 44.75 लाख लोग रहते हैं। अब तक लगभग 40 हजार संपत्तियों के लिए कन्वेयंस डीड (स्वामित्व का प्रमाण) या ऑथराइजेशन स्लिप जारी की जा चुकी हैं।

'हनुमान अंश' की टीम को गांधी स्मृति में 'साइटेशन ऑफ ऑनर' से सम्मान

नई दिल्ली, साहस समाचार।

फिल्म 'शिरडी साईं बाबा' के निर्माता और शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के संस्थापक एवं मैनेजिंग ट्रस्टी औषिम खेरतपाल ने गांधी स्मृति में आयोजित विशेष समारोह में फिल्म 'हनुमान अंश' के कलाकारों, निर्माता और निर्देशक को 'साइटेशन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया। समारोह का आयोजन शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के संयुक्त तत्वावधान में किया गया।

कार्यक्रम में गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष विजय गोयल, शिरडी लोकसभा क्षेत्र के सांसद भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, शिरडी साईं बाबा फाउंडेशन के संस्थापक औषिम खेरतपाल और साईं बाबा पीस अवॉर्ड्स की इंटरनेशनल स्ट्रैटेजिस्ट संजना जॉन मौजूद रहीं। फिल्म 'हनुमान अंश' के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी, मुख्य अभिनेता शोभिनव सत्य, बाल कलाकार विहान शेगड़े तथा निर्माता नम्रता और रागिनी सोना सहित फिल्म की टीम ने समारोह में हिस्सा लिया।

इस अवसर पर औषिम खेरतपाल ने कहा कि करीब 26 वर्ष पहले उन्होंने साईं बाबा के जीवन और संदेशों को केंद्र में रखकर फिल्म 'शिरडी साईं बाबा' बनाई थी। उनका उद्देश्य साईं बाबा के संदेशों और जनकल्याण की भावना को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। उन्होंने कहा कि 'हनुमान अंश' की टीम ने भी आस्था और आध्यात्मिक चेतना से जुड़े विषय को सिनेमा के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है।

खेरतपाल ने कहा कि सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि इसके जरिए समाज में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति जागरूकता भी पैदा की जा सकती है। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को सम्मानित करते हुए उनके प्रयासों की सराहना की।

विजय गोयल ने कहा कि 'हनुमान अंश' जैसी फिल्में भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम बन सकती हैं। उन्होंने गांधी स्मृति परिसर में फिल्म की टीम के सम्मान को विशेष अवसर बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़े विषयों पर सार्थक सिनेमा को प्रोत्साहित करते हैं।

समारोह में फिल्म के बाल कलाकार विहान शेगड़े का विशेष उल्लेख किया गया, जिन्होंने 'हनुमान अंश' में 14 वर्षीय बाबा की भूमिका निभाई है। कार्यक्रम के दौरान फिल्म की पूरी टीम को 'साइटेशन ऑफ ऑनर' प्रदान किया गया।

इहबास में विश्व अल्जाइमर दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम हुए

नई दिल्ली,एजेंसी।

विश्व अल्जाइमर दिवस के अवसर पर इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) के न्यूरोबिहेवियर क्लीनिक ने डिमेंशिया और अल्जाइमर रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में मरीजों, उनके परिजनों और देखभाल करने वालों को बीमारी की समझ व देखभाल का महत्व बताया गया। मरीजों के लिए जागरूकता सत्र और संज्ञानात्मक गतिविधियां हुईं। देखभाल करने वालों हेतु सहायता सत्र व म्यूजिक थेरेपी हुई। देखभाल की चुनौतियों व मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। कॉग्निशन मास्टरक्लास के जरिये मस्तिष्क स्वास्थ्य व डिमेंशिया पर जानकारी साझा की गई।

एनयूजेआई के राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियां जोरों पर

नई दिल्ली,एजेंसी।

नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स इंडिया (एनयूजेआई) का तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 28 से 30 नवंबर तक राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अधिवेशन में देशभर से सैकड़ों पत्रकार शामिल होंगे और पत्रकारों की समस्याओं, अधिकारों तथा उनके हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर गंभीर एवं सार्थक चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय अधिवेशन को सफल और भव्य बनाने के लिए एनयूजेआई की राज्य इकाइयों ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

एनयूजेआई की नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कार्यकारिणी की पहली बैठक 25 सितंबर को नई दिल्ली स्थित 7, जंतर-मंतर रोड स्थित संगठन के मुख्यालय में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश थपलियाल ने की। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा विभिन्न राज्य इकाइयों के अध्यक्ष और महासचिव भी शामिल हुए।

अवैध नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई से मिलेगा लाभ: विनीत जैन

नई दिल्ली,एजेंसी।

राजधानी में अवैध शराब की बिक्री, तस्करी और नशे के कारोबार के खिलाफ दिल्ली सरकार और आबकारी विभाग की कार्रवाई का शाहदरा जिला भाजपा प्रवक्ता विनीत जैन ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई का लाभ आने वाले समय में दिल्ली की जनता, विशेषकर युवाओं को मिलेगा। विनीत जैन ने कहा कि अवैध शराब के मामलों में प्राथमिकी, गिरफ्तारियां, वाहनों की जब्ती और शराब की बरामदगी से सरकार की सख्ती दिखाई देती है। उनके अनुसार, अप्रैल से अगस्त 2026 के बीच आबकारी विभाग ने 725 प्राथमिकी दर्ज कर 730 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 197 वाहन जब्त किए गए और करीब 2.20 लाख बोतल अवैध शराब बरामद की गई। उन्होंने कहा कि अवैध नशे का कारोबार केवल कानून-व्यवस्था का विषय नहीं है।

बल्कि इसका समाज और युवाओं के भविष्य पर भी असर पड़ता है। इसलिए अवैध शराब की आपूर्ति और परिवहन पर कार्रवाई के साथ पूरे आपूर्ति तंत्र को समाप्त करने की दिशा में प्रयास जरूरी हैं। जैन ने कहा कि दिल्ली के प्रवेश मार्गों, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख परिवहन मार्गों पर निगरानी और मजबूत की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियमित निगरानी और सख्त कार्रवाई से अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के साथ अपराध की रोकथाम और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने में मदद मिलेगी। उन्होंने सरकार से अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान को आगे भी पूरी गंभीरता से जारी रखने की अपील की।

दिल्ली पुलिस ने दो शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली,एजेंसी।

पश्चिमी जिले की दिल्ली पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। तिलक विहार पुलिस पोस्ट की टीम ने इलाके में गश्त के दौरान दो शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से चोरी की पांच दोपहिया गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिससे वाहन चोरी के पांच मामलों का खुलासा हुआ है। वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी हरेश्वर वी. स्वामी द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई 26 सितंबर को की गई। एसआई तरुण (इंचार्ज, पीपी तिलक विहार) के नेतृत्व में एक गश्ती टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल महेश, धर्मबीर और शमशेर शामिल थे, थाना तिलक नगर इलाके में गश्त पर थी।

यह पूरी कार्रवाई एसएचओ थाना तिलक नगर और एसीपी तिलक नगर के नेतृत्व और डीसीपी की देखरेख में हुई।गश्त के दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली कि वाहन चोरी में शामिल दो लोग चोरी की दोपहिया गाड़ी बेचने के लिए तिलक विहार के बी-ब्लॉक स्थित श्मशान घाट के पास आने वाले हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए टीम ने मौके पर जाल बिछाया। सुबह लगभग 04:15 बजे दो लोगों को एक दोपहिया गाड़ी पर आते देखा गया और उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ में उनकी पहचान इंद्रपाल सिंह उर्फ प्रिंस और गगनजोत सिंह उर्फ गोगीके रूप में हुई। दोनों दिल्ली के रहने वाले हैं।

जब पुलिस ने उनसे गाड़ी के कागजात मांगे तो वे कोई दस्तावेज नहीं दिखा सके। जांच में पता चला कि उनके पास मौजूद स्कूटी चोरी की है, जिसकी ई-एफआईआर तिलक नगर थाने में दर्ज थी। लगातार पूछताछ में दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि वे थाना तिलक नगर और अन्य थानों के इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी करते थे। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने तीन और चोरी की मोटरसाइकिलें और एक स्कूटी बरामद की।

नो यूपीआई डे' का आह्वान नहीं किया: कैट

नई दिल्ली,एजेंसी।

व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने स्पष्ट किया है कि उसने 'नो यूपीआई डे' मनाने या इसका आह्वान करने का कोई फैसला नहीं किया है। संगठन ने कहा कि न तो उसने ऐसा कोई अभियान घोषित किया है और न ही इस तरह के किसी आयोजन का समर्थन या उसमें शामिल होने का निर्णय लिया है। रविवार को वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें कैट द्वारा किए गए पोस्ट का हवाला देते हुए कहा कि दो अक्तूबर को 'नो यूपीआई डे' के संबंध में संगठन की तरफ से कोई आह्वान नहीं किया गया है।

कैट ने कहा कि उसके नाम से नो यूपीआई डे को लेकर प्रसारित की जा रही जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है। संगठन ने व्यापारियों और आम लोगों से ऐसी जानकारी पर भरोसा नहीं करने और किसी भी दावे की पुष्टि आधिकारिक माध्यमों से करने की अपील की है। उधर, सूत्रों का कहना है कि यूपीआई पर एमडीआर लगाए जाने के संबंध में वित्त मंत्रालय की तरफ से भी व्यापारिक संगठनों से बात की जा रही है। आने वाले दिनों में भी कुछ अन्य संगठनों के साथ मंत्रालय स्तर पर बैठक हो सकती है। मोबाइल रिटेलर्स का विरोध: यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर शुल्क लगाने के विरोध में देश भर के मोबाइल फोन खुदरा विक्रेता दो अक्तूबर को 'नो यूपीआई डे' मनाने की योजना बना रहे हैं। उद्योग निकाय एआईएमआरए के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि इस दिन यूपीआई से लेनदेन नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन (एआईएमआरए) के उपाध्यक्ष और दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के अध्यक्ष तरविंदर सिंह ने बयान में कहा, एआईएमआरए ने यूपीआई लेनदेन पर लागू 0.4 प्रतिशत एमडीआर को लेकर मोबाइल खुदरा विक्रेताओं की चिंताओं को बताने के लिए दो अक्तूबर 2026 को 'नो यूपीआई डे' का आह्वान किया है।

फॉर्म-6 ही मुख्य मुद्दा, सीईसी पद की गरिमा को ही खत्म कर दिया: उदित राज

नई दिल्ली,एजेंसी।

चुनाव आयोग में अंदरूनी असहमति के मुद्दे को लेकर सियासी घमासान के बीच शनिवार को चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी मौजूद रहे। बैठक के बाद फॉर्म-6 विवाद को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि यह मुख्य मुद्दा नहीं है। इस बयान पर कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उदित राज ने कहा कि फॉर्म-6 ही सबसे बड़ा और मुख्य मुद्दा है। उन्होंने कहा कि 1960 के नियम के अनुसार फॉर्म-6 में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। वोटर बनने के लिए सिर्फ तीन शर्तें जरूरी हैं — व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, 6 महीने से वह उस जगह का निवासी हो और वह वोटर बनने के लिए योग्य हो।

उदित राज ने कहा कि एसआईआर का कोई कानूनी आधार ही नहीं है। यह न तो 1950 के नियम में है और न ही 1960 के नियम में। उन्होंने आरोप लगाया कि फॉर्म-6 की हार्ड कॉपी में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म में बदलाव कर दिया गया है। इस बदलाव को कोई नहीं कर सकता। चुनाव आयोग के अंदर भी इस मुद्दे पर मतभेद है। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने इस पर लिखित में अपनी असहमति जताई थी, लेकिन अभी तक उसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा के उस आरोप पर कि कांग्रेस अपने राजनीतिक हितों के लिए संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को नुकसान पहुंचा रही है, उदित राज ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो संवैधानिक संस्थाओं की रक्षा के लिए जी-जान से लड़ाई लड़ रही है। भाजपा उल्टी बात कर रही है। उन्होंने कहा कि फॉर्म-6 में जो बदलाव किया गया है, उसके अनुसार अब 18 साल के युवाओं को वोटर बनने के लिए 2002 की वोटर लिस्ट में अपने माता-पिता या दादा-दादी का नाम दिखाना होगा। ऐसे में कोई भी नया वोटर नहीं बन पाएगा। 2002-2003 की वोटर लिस्ट से लिंक करने के कारण करोड़ों लोग वोटर नहीं बन पा रहे हैं, जबकि नियम के अनुसार सिर्फ 18 वर्ष की उम्र, भारतीय नागरिकता और उस क्षेत्र का सामान्य निवासी होना ही पर्याप्त है।

भाजपा सांसद संबित पात्रा के राहुल गांधी पर लगाए गए आरोप कि वह सत्ता न मिलने के कारण चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं, पर उदित राज ने कहा कि 2014 के बाद ऐसी कोई संस्था नहीं बची जिसे भाजपा ने निशाना न बनाया हो। उन्होंने आरोप लगाया कि 13 करोड़ 80 लाख वोटरों का नाम काटकर लोकसभा 2024, बिहार, बंगाल, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र के चुनावों में बेईमानी से जीत हासिल की गई है। संविधान और उसकी संस्थाओं की रक्षा राहुल गांधी, कांग्रेस और पूरा विपक्ष कर रहा है।

यह उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर हमला बोलते हुए उदित राज ने कहा कि उन्होंने गैर-कानूनी काम किया है और उन्हें तुरंत जेल भेजना चाहिए। उन्होंने हजार अपराधियों से भी बड़ा अपराध किया है।

1,850 करोड़ जारी होने के बावजूद जनता को नहीं मिला पूरा लाभ: जीनवाल

नई दिल्ली,एजेंसी।

दिल्ली के 3 शहरी निकायों के लिए 2026-27 के आधारभूत कर आवंटन की दूसरी किस्त के रूप में 1,850.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इसमें नगर निगम दिल्ली को 1,820.40 करोड़, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को 17.95 करोड़ और दिल्ली छावनी बोर्ड को 12.31 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि कचरा प्रबंधन, सड़कों, स्ट्रीट लाइट, पार्क, प्राथमिक विद्यालयों और स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च की जानी है।

इस राशि को लेकर आम आदमी पार्टी की सुंदर नगरी वार्ड की निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बड़ी राशि जारी करने और घोषणाएं करने को उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जबकि कई वार्डों में सड़क, सफाई, जलभराव और स्ट्रीट लाइट जैसी स्थानीय समस्याएं बनी हुई हैं।

जीनवाल ने कहा कि करोड़ों रुपये जारी होना अपने आप में विकास की गारंटी नहीं है। सरकार को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि किस वार्ड में कितनी राशि खर्च की गई और उससे कौन-कौन से कार्य कराए गए। उन्होंने सरकारी धन के उपयोग का सार्वजनिक लेखा परीक्षण और वार्डवार खर्च का विवरण सामने रखने की मांग की। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आधारभूत कर आवंटन के तहत कुल 3,701.32 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इसकी पहली किस्त के रूप में 925.33 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि दूसरी किस्त 1,850.66 करोड़ रुपये की है। शेष 925.33 करोड़ रुपये अंतिम चरण में जारी किए जाने हैं।

RNI.No DLHIN/25/A2841

स्वामी, प्रकाशक, संपादक देवेंद्र सिंह तोमर एवं मुद्रक रवि भारद्वाज मै. मारुती नंदन प्रिंटर्स एवं पब्लिशर, शक्ति कॉम्प्लेक्स 6/18, समयपुर इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली 110042 से मुद्रित एवं हॉउस नंबर 16/ 9980, गली नंबर-5, सराय रोहिल्ला न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005 से प्रकाशित।

संपादकीय कार्यालय - B4/265B केशव पुरम नई दिल्ली -110005। फोन-011-40106508 मोबाइल-9911466900/ 8076353913। Email.saahassamachardainik@gmail.com

संपादक देवेंद्र सिंह तोमर

इस अंक में प्रकाशित खबरों एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। किसी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा नई दिल्ली के न्यायालय में होगा।

दिल्ली सरकार का उद्देश्य बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है: रेखा गुप्ता

मुख्यमंत्री ने अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ के विकास कार्यों का किया शिलान्यास।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेवा संकल्प अभियान के तहत रविवार को किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट की अनधिकृत कॉलोनियों में 214.12 करोड़ रुपये के 53 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इन कार्यों से लगभग 1 लाख 75 हजार लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इस अवसर पर सांसद योगेंद्र चांदोलिया, दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री प्रवेश साहिब सिंह, शिक्षा मंत्री आशीष सूद, समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज और विधायक राज करण, मनोज शौकीन, गजेंद्र दराल सहित उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार का उद्देश्य दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में बुनियादी नागरिक सुविधाओं को मजबूत करना है। लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे क्षेत्रों में अब योजनाबद्ध तरीके से विकास कार्य किए जा रहे हैं। सड़क, नाली, सीवेज और ड्रेनेज जैसी मूलभूत सुविधाएं प्रत्येक नागरिक का अधिकार हैं। इन 53 विकास कार्यों के अंतर्गत 27 अनधिकृत कॉलोनियों में 1,062 सड़कों और गलियों का विकास किया जाएगा। इसके साथ ही लगभग 89.82 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 147.69 किलोमीटर ड्रेनेज नेटवर्क विकसित किया जाएगा।

इससे स्थानीय आवागमन बेहतर होने के साथ-साथ जल निकासी की व्यवस्था मजबूत होगी और जलभराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 27 वर्षों बाद हुए सत्ता परिवर्तन के बाद विकास कार्यों को नई गति मिली है। सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि वर्षों से लंबित समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं है बल्कि उन्हें समयबद्ध तरीके से जमीन पर उतारने और जनता को उनका सीधा लाभ पहुंचाने पर जोर दे रही है। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क और ड्रेनेज जैसी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि विकास की रफ्तार अब केवल मुख्य सड़कों तक सीमित न रहे बल्कि अनधिकृत कॉलोनियों की हर गली और हर घर तक पहुंच रही है। किराड़ी, बवाना, मुंडका, नरेला और नांगलोई जाट में शुरू किए गए 214.12 करोड़ रुपये के 53 विकास कार्य वर्षों से लंबित मूलभूत समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। सड़क, सीवर और ड्रेनेज व्यवस्था को मजबूत कर हम इन क्षेत्रों को बेहतर और सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं।

मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने कहा कि किराड़ी क्षेत्र में पिछली सरकार के कार्यकाल में विकास कार्यों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। आम आदमी पार्टी की सरकार लंबे समय तक सत्ता में रही और आज भी किराड़ी से आम आदमी पार्टी (आआपा) के विधायक हैं लेकिन क्षेत्र में अपेक्षित विकास कार्य नहीं हुए। उन्होंने कहा कि आज मुख्यमंत्री ने 105 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराकर यह सुनिश्चित किया है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में विधायक आआपा का हो या भाजपा का विकास कार्यों और बजट आवंटन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए।

बात मुद्दे की

आलोक गौड़

सवाल चुनाव आयोग पर, घिरती मोदी सरकार

नई दिल्ली। जिस चुनाव आयोग को लेकर अब तक विपक्ष सवाल पूछ रहा था, अब उसी आयोग पर मोदी सरकार के अपने सहयोगी दल सवाल खड़े कर रहे हैं। यही इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि जब विपक्ष की आवाज को राजनीतिक आरोप बताकर खारिज किया जा सकता है, तब सरकार के साथ खड़े चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा की चिंता को उसी आसानी से खारिज करना मुश्किल होगा।

तीनों दलों ने चुनाव आयोग से एसआईआर को लेकर उठ रहे सवालों पर स्थिति स्पष्ट करने, भ्रम दूर करने और जनता का विश्वास बनाए रखने की जरूरत बताई है। यानी सवाल अब केवल विपक्ष का नहीं रह गया। सवाल सत्ता के उस खेमे के भीतर भी पहुंच गया है, जिसके सहारे नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है।

यही वजह है कि मामला अब सिर्फ चुनाव आयोग बनाम विपक्ष नहीं है। सवाल चुनाव आयोग पर है और उसकी राजनीतिक आंच मोदी सरकार तक पहुंच रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सहयोगी दलों ने ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग नहीं की। उन्होंने चुनाव आयोग से स्पष्टीकरण मांगा है। सुनने में यह मामूली अंतर लग सकता है, लेकिन लोकतंत्र में इसका अर्थ बहुत बड़ा है। क्योंकि सहयोगी दल यह कह रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर जनता के मन में यदि संदेह पैदा हो रहा है तो उसे दूर करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है।

चिराग पासवान ने कहा कि चुनावी व्यवस्था पर लोगों का भरोसा कम होना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं होगा और आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा ने भी एसआईआर को लेकर पैदा हुए भ्रम को दूर करने की जरूरत बताई। टीडीपी ने भी पारदर्शिता और जनता के विश्वास को महत्वपूर्ण बताया।

तो सवाल यह है कि आखिर वह कौन-सी स्थिति है जिसने सरकार के सहयोगियों को भी चुनाव आयोग से जवाब मांगने के लिए मजबूर किया? क्योंकि मामला सिर्फ एसआईआर तक सीमित नहीं है।

चुनाव आयोग के भीतर कामकाज को लेकर उठे सवालों ने इस विवाद को और गंभीर बना दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले दस महीनों में कम से कम 14 बार आयोग के भीतर कुछ फैसलों और आदेशों पर औपचारिक आपत्तियां दर्ज कराईं। रिपोर्ट में कहा गया कि कुछ मामलों में दोनों चुनाव आयुक्तों ने उन्हें पर्याप्त जानकारी दिए बिना फैसले लिए जाने सहित कई मुद्दों पर सवाल उठाए।

अब चुनाव आयोग की ओर से यह सफाई दी गई है कि अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए। ठीक है। लेकिन फिर सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर फैसले सर्वसम्मति से लिए गए तो उन 14 आपत्तियों की प्रकृति क्या थी? किन मुद्दों पर आपत्ति हुई? आपत्तियों का समाधान कैसे हुआ? क्या उन आपत्तियों को स्वीकार किया गया या खारिज?

अगर खारिज किया गया तो उसके कारण क्या थे?

और अगर सब कुछ सामान्य संस्थागत विमर्श था तो जनता को यह जानने में परेशानी क्यों होनी चाहिए कि आयोग के भीतर मतभेद या आपत्तियां किस मुद्दे पर उठीं? यही वह जगह है जहां पारदर्शिता की जरूरत सबसे ज्यादा है। चुनाव आयोग कोई सामान्य सरकारी विभाग नहीं है। यह वह संवैधानिक संस्था है जिसके फैसले पर सरकारें बनती हैं, सरकारें जाती हैं और राजनीतिक दल अपनी जीत-हार स्वीकार करते हैं।इसलिए चुनाव आयोग पर सवाल उठना अपने आप में लोकतंत्र का संकट नहीं है। लेकिन सवालों के जवाब न मिलना जरूर संकट पैदा कर सकता है। एसआईआर को लेकर भी मूल सवाल यही है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण जरूरी है। मृत मतदाताओं के नाम हटने चाहिए। दोहरे नाम हटने चाहिए। अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के बीच एक सवाल सबसे ऊपर रहना चाहिए कि कहीं किसी वास्तविक मतदाता का नाम तो नहीं कट रहा? क्योंकि किसी अपात्र व्यक्ति का नाम हटना चुनावी सूची की सफाई है, लेकिन किसी पात्र नागरिक का नाम गलती से हट जाना उसके लोकतांत्रिक अधिकार पर सीधा प्रहार है।

इसलिए एसआईआर की सफलता केवल इस बात से तय नहीं हो सकती कि कितने नाम हटाए गए। यह भी देखना होगा कि कितने वास्तविक मतदाता सूची से बाहर हुए। कितनों को नोटिस मिला।

कितनों को जवाब देने का अवसर मिला। कितनों के जवाब स्वीकार हुए। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति का नाम हटाया गया, उसे अपनी नागरिकता और मताधिकार साबित करने के लिए ऐसी प्रक्रिया से तो नहीं गुजरना पड़ा जो उसके लिए असंभव या अत्यधिक कठिन हो। यही वजह है कि चुनाव आयोग को सवालों से घबराने के बजाय उन्हें सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि चुनाव आयोग का अधिकार उसकी संवैधानिक स्थिति से आता है, लेकिन उसकी विश्वसनीयता जनता के भरोसे से आती है। और यहीं मोदी सरकार की मुश्किल शुरू होती है। अब तक सरकार के सामने विपक्ष था। सरकार कह सकती थी कि विपक्ष चुनाव आयोग को बदनाम कर रहा है। राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं तो उसे राजनीतिक अभियान बताया जा सकता था। एसआईआर पर कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दलों के आरोपों को राजनीतिक स्वार्थ से जोड़कर देखा जा सकता था। लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। जब चिराग पासवान सवाल उठाते हैं, जब टीडीपी पारदर्शिता की बात करती है, जब उपेंद्र कुशवाहा भ्रम दूर करने की मांग करते हैं, तब इसे केवल विपक्ष की राजनीति कहकर खत्म नहीं किया जा सकता।

‘मन की बात’ के सामूहिक श्रवण में दिखी भाजपा की संगठनात्मक ताकत

जिला कार्यालय में जुटे वरिष्ठ नेता, पार्षद और कार्यकर्ता; धर्मवीर सिंह ने बूथ स्तर तक प्रधानमंत्री का संदेश पहुंचाने का किया आह्वान

नई दिल्ली, साहस समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ के 138वें एपिसोड के सामूहिक श्रवण के दौरान रविवार को नई दिल्ली जिला भाजपा कार्यालय में पार्टी की जमीनी संगठनात्मक सक्रियता नजर आई। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं से लेकर मंडल और बूथ स्तर के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। साउथ जोन चेयरमैन धर्मवीर सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद विनोद तावड़े, सांसद बांसुरी स्वराज, दिल्ली प्रदेश भाजपा महामंत्री पवन राणा, विधायक अनिल शर्मा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं मालवीय नगर विधायक सतीश उपाध्याय, विधायक शिखा राय और नई दिल्ली जिला अध्यक्ष रविंदर चौधरी समेत निगम पार्षद, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

धर्मवीर सिंह ने कहा कि ‘मन की बात’ प्रधानमंत्री और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है। सामान्य नागरिकों के प्रयासों को राष्ट्रीय मंच मिलने से जनभागीदारी और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना मजबूत होती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के संदेश को केवल सुनने तक सीमित रखने के बजाय कार्यकर्ता उसे अपने-अपने क्षेत्रों में पहुंचाएं और समाजसेवा के कार्यों को गति दें।

उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और पहलों की जानकारी लोगों तक पहुंचाने को कहा। धर्मवीर सिंह ने कहा कि भाजपा का संगठन केवल चुनावी गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि जनता के बीच लगातार सक्रिय रहकर काम करता है।

कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने समाजसेवा और राष्ट्रहित से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प।

युवा को थप्पड़ मारने के आरोप पर आप ने प्रवेश वर्मा पर साधा निशाना

कहा- दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करे, भाजपा मंत्री को कैबिनेट से हटाए

नई दिल्ली, साहस समाचार।

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) मंत्री प्रवेश वर्मा पर एक युवक को कथित तौर पर थप्पड़ मारने को लेकर निशाना साधा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज ने आरोप लगाया कि तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में सड़क की गुणवत्ता को लेकर सवाल पूछने और वीडियो बनाने की कोशिश करने पर मंत्री ने युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट और गाली-गलौज की।

भारद्वाज ने रविवार को जारी बयान में कहा कि तिलक नगर में PWD की ओर से बनाई गई सड़क की गुणवत्ता को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी थी। उनके मुताबिक, इसी मुद्दे पर एक युवक ने मंत्री प्रवेश वर्मा से सवाल किया और घटना का वीडियो बनाने का प्रयास किया। आरोप है कि इस दौरान मंत्री ने भीड़ के बीच युवक को थप्पड़ मार दिया और उसके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया।

आप प्रवक्ता ने कहा कि किसी जनप्रतिनिधि द्वारा सवाल पूछने वाले नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने दिल्ली पुलिस से प्रवेश वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।

भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और भाजपा पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि पीडब्लूडी के कामकाज को लेकर जनता द्वारा सवाल उठाए जाने पर मंत्री को जवाब देना चाहिए था, न कि सवाल पूछने वाले युवक के साथ कथित तौर पर मारपीट करनी चाहिए थी।

उन्होंने भाजपा नेतृत्व से प्रवेश वर्मा को दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल से हटाने और पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग की। भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से इस मामले में कार्रवाई करने की अपील की।

कछुआ तस्करी मामले में मणिवन्नन रिहा, भारत में चलेगी जांच

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली हाई कोर्ट ने थाईलैंड में 840 रेडिएटेड कछुओं की तस्करी के मामले में वांछित मुरुगेसन मणिवन्नन को रिहा करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि उसे थाईलैंड प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा और मामले की जांच भारत में सीबीआई करेगी। अदालत ने कहा कि जब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि मणिवन्नन का प्रत्यर्पण नहीं किया जाना है, तो प्रत्यर्पण आदेश के आधार पर उसकी हिरासत जारी नहीं रखी जा सकती। अदालत ने निर्देश दिया कि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न होने पर उसे तत्काल जेल से रिहा किया जाए।

मणिवन्नन को 6 जनवरी 2026 को पटियाला हाउस अदालत ने थाईलैंड प्रत्यर्पित किए जाने तक हिरासत में रखने का आदेश दिया था। हालांकि, निर्धारित अवधि में उसे भारत से बाहर नहीं भेजा गया। थाईलैंड के अनुरोध के अनुसार, मणिवन्नन को 27 अगस्त 2012 को बैंकाक के सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर 840 रेडिएटेड कछुओं के साथ पकड़ा गया था। उसके खिलाफ वन्यजीव संरक्षण, पशु महामारी और सीमा शुल्क कानूनों के तहत मामले दर्ज किए गए थे। बाद में वह थाईलैंड से भारत लौट आया। उसके खिलाफ 4 अप्रैल 2014 को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।

चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी नेताओं की गतिविधियां देशद्रोह से कम नहीं: रेखा गुप्ता

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में जनता का विश्वास बनाए रखना सभी राजनीतिक दलों और नेताओं की जिम्मेदारी है। उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं की बातें देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर देशद्रोह का केस लगना चाहिए। मुख्यमंत्री ने रविवार को जनसेवा सदन में आयोजित पत्रकार वार्ता में विपक्षी नेताओं के लगाए जा रहे अनर्गल आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस पारदर्शिता के साथ चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया और निर्णयों को जनता के सामने रख रहा है, क्या विपक्ष के शासनकाल में चुनाव आयोग इसी प्रकार पारदर्शी तरीके से काम करता था?

उन्होंने कहा कि मात्र एक अखबार में प्रकाशित खबर के आधार पर बेबुनियाद माहौल पैदा करना क्या विपक्ष को शोभा देता है? चुनाव आयोग ने एक-एक विषय को पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के सामने रखा और स्पष्ट किया है कि निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सवाल पूछने का अधिकार सभी को है, लेकिन सवाल तथ्यों के आधार पर होने चाहिए। केवल राजनीतिक आरोप लगाकर किसी संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री ने फॉर्म-6 को लेकर विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-6 को लेकर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि मूल फॉर्म में बदलाव नहीं किया गया है। एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित घोषणा को अलग से जोड़ा गया है। चुनाव आयोग के नागरिक सेवा पोर्टल पर वर्तमान में भी नए मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 और उससे संबंधित घोषणा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और सुलभ बनाया जा रहा है।

मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य पात्र मतदाताओं को सूची में बनाए रखना तथा मृत, स्थानांतरित, डुप्लीकेट अथवा अन्य कारणों से अपात्र हो चुकी प्रविष्टियों को नियमानुसार सत्यापित करना है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष के ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर कहा कि मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया में वर्षों से मृत हो चुके व्यक्तियों, डुप्लीकेट प्रविष्टियों, स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं और अन्य कारणों से अमान्य हो चुकी प्रविष्टियों की पहचान की जाती है। उन्होंने कहा कि वास्तविक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में बने रहें और अपात्र या डुप्लीकेट नाम हटाए जाएं, यह चुनावी प्रक्रिया की स्वाभाविक आवश्यकता है।

चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया में भी मतदाता सूची के सत्यापन, दावों और आपत्तियों के लिए निर्धारित प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों पहले जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी।

सड़क की गुणवत्ता पर भिड़े मंत्री और विधायक

घटना के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो भी सामने आया है।

नई दिल्ली,साहस समाचार।

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में सड़क की गुणवत्ता को लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश साहिब सिंह और आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह के बीच तीखी बहस का मामला सामने आया है। घटना के दौरान एक युवक को थप्पड़ मारे जाने का वीडियो भी सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि मंत्री ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाए जाने के बाद वहां मौजूद युवक को थप्पड़ मारा। घटना को लेकर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है।

मिली जानकारी के अनुसार, तिलक नगर क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण के दौरान मंत्री परवेश साहिब सिंह और स्थानीय विधायक जरनैल सिंह आमने-सामने आ गए। दोनों के बीच सड़क की गुणवत्ता को लेकर तीखी बहस हुई। सामने आए वीडियो में जरनैल सिंह सड़क की ऊपरी परत को हाथ से उखाड़ते दिखाई दे रहे हैं। वह उखड़ी हुई सड़क का हिस्सा मंत्री को दिखाते हुए निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हैं। विधायक का कहना था कि सड़क इतनी कमजोर है कि उसे हाथ से ही उखाड़ा जा सकता है।

वीडियो में दोनों पक्षों के बीच सड़क निर्माण को लेकर बहस होती दिखाई देती है। इस दौरान परवेश साहिब सिंह की ओर से यह कहते हुए सुना जाता है कि लंबे समय से सड़क का निर्माण नहीं हुआ और अब निर्माण कराया जा रहा है। इसके जवाब में जरनैल सिंह ने सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए कहा कि सड़क ऐसी नहीं होनी चाहिए जो थोड़े समय में ही खराब हो जाए। बहस के दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पूरे घटनाक्रम की वीडियो रिकॉर्डिंग की। बहस के बाद मंत्री वहां से आगे बढ़ने लगे।

इसी दौरान जरनैल सिंह ने सड़क की एक और परत उखाड़ी और उसे हाथ में लेकर मंत्री की ओर बढ़े। वीडियो में वह अन्य लोगों के साथ मंत्री के पीछे जाते दिखाई देते हैं। मौके पर मौजूद लोगों की भीड़ के बीच एक युवक मोबाइल फोन से घटनाक्रम की रिकॉर्डिंग कर रहा था। इसी दौरान मंत्री और युवक के बीच हाथापाई जैसी स्थिति बनी और मंत्री द्वारा युवक को थप्पड़ मारे जाने का दृश्य वीडियो में दिखाई देता है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, युवक ने आरोप लगाया कि वह विधायक के सामाजिक माध्यम के लिए घटनाक्रम का सीधा प्रसारण कर रहा था। उसके मुताबिक, मंत्री ने उसका फोन छीनने की कोशिश की और उसे थप्पड़ मारा। युवक ने मामले में शिकायत किए जाने की बात भी कही है। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने घटना का वीडियो साझा करते हुए मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाए जाने के बाद मंत्री ने वहां मौजूद कैमरा संचालक को थप्पड़ मारा।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी के अनुसार घटना को लेकर मंत्री परवेश साहिब सिंह की ओर से तत्काल कोई विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई थी। ऐसे में थप्पड़ मारे जाने की परिस्थितियों को लेकर दोनों पक्षों के दावों को अलग-अलग देखा जाना जरूरी है। घटना के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि वह स्वयं तिलक नगर जाकर सड़क की स्थिति का निरीक्षण करेंगे।

केजरीवाल ने आरोप लगाया कि सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब थी और स्थानीय लोगों द्वारा इसकी स्थिति मंत्री को दिखाए जाने के दौरान युवक के साथ मारपीट की गई।

22 मामलों में वांछित अपराधी 1.38 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार

नई दिल्ली,साहस समाचार।

राजधानी में नशे के कारोबार पर लगाम कसने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कवच के तहत सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पटेल नगर थाना पुलिस ने एक खतरनाक अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 1.380 किलो गांजा बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी, डकैती और आर्म्स एक्ट समेत 22 आपराधिक मामले दर्ज हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी रोहित राजबीर सिंह के निर्देश पर ऑपरेशन कवच के तहत ड्रग्स बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 25 सितंबर 2026 को पटेल नगर पुलिस की एक विशेष टीम गश्त पर थी।

पुलिस टीम जब शादीपुर फ्लाईओवर, बलजीत नगर के पास पहुंची, तो उन्हें एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली तो उसके पास से 1.380 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान राहुल राय उर्फ आर्यन उर्फ रोहित (उम्र करीब 30 साल) के रूप में हुई है। वह मूल रूप से गांव चंदपुरा, पोस्ट पतेपुर, थाना बाली गांव, जिला वैशाली, बिहार का रहने वाला है। मौके पर ही एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत थाना पटेल नगर में एफआईआर दर्ज कर नशीला पदार्थ जब्त कर लिया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

यह पूरी कार्रवाई पटेल नगर थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर नवीन कुमार के नेतृत्व में और एसीपी सुनील कुमार की देखरेख में की गई। टीम में पीएसआई सागर सोलंकी, हेड कांस्टेबल हरपाल, हेड कांस्टेबल अजय, कांस्टेबल धर्मेंद्र और कांस्टेबल दिलीप शामिल थे। टीम ने पूरी सतर्कता के साथ आरोपी को दबोचा। पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है।

संपादकीय

सुविधा के नाम पर क्या हमने अपना सुकून भी खो दिया?

देवेंद्र सिंह तोमर

आज की दुनिया को अगर एक शब्द में परिभाषित करना हो तो शायद वह शब्द होगा 'तुरंत'। खाना चाहिए तो कुछ मिनटों में घर पहुंच जाता है। सामान चाहिए तो कुछ घंटों में दरवाजे पर दस्तक हो जाती है। बैंक का काम हो, टिकट बुक करना हो, पैसे भेजने हों या किसी से बात करनी हो, सब कुछ मोबाइल की एक स्क्रीन पर उपलब्ध है। तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस सुविधा के बीच एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है क्या सुविधा बढ़ने के साथ हमारा सुकून कम होता जा रहा है? एक समय था जब किसी से मिलने के लिए लोग उसके घर जाते थे। बातचीत के लिए समय निकालना पड़ता था। चिट्ठी लिखी जाती थी तो जवाब का इंतजार होता था। बाजार जाना पड़ता था तो रास्ते में लोगों से मुलाकात होती थी। आज संपर्क के साधन बढ़ गए हैं, लेकिन संवाद कम होता दिखाई देता है। हमारे हाथ में दुनिया भर की जानकारी है, लेकिन अपने आसपास बैठे व्यक्ति के लिए हमारे पास समय नहीं है।

तकनीक ने दूरी कम की है, लेकिन कई बार रिश्तों के बीच एक अदृश्य दूरी भी पैदा कर दी है। परिवार एक ही कमरे में बैठा होता है, लेकिन हर व्यक्ति अपनी-अपनी स्क्रीन में व्यस्त दिखाई देता है। बच्चे माता-पिता से ज्यादा समय मोबाइल के साथ बिताते हैं और माता-पिता भी काम, संदेश, समाचार और सामाजिक माध्यमों की दुनिया में उलझे रहते हैं। घर में लोग साथ हैं, लेकिन मन अलग-अलग जगहों पर भटक रहा है।

सबसे बड़ी समस्या शायद यह नहीं है कि हमारे पास सुविधाएं बहुत ज्यादा हैं। समस्या यह है कि हमने सुविधा को अपनी जरूरत और जरूरत को अपनी आदत बना लिया है। पहले जो काम करने में थोड़ा समय लगता था, अब उसमें कुछ मिनट भी लग जाएं तो हमें बेचैनी होने लगती है। भोजन आने में देर हो जाए तो शिकायत, यातायात में कुछ मिनट रुकना पड़े तो गुस्सा, संदेश का जवाब तुरंत न मिले तो नाराजगी और किसी काम के परिणाम में समय लगे तो अधीरता।

हमने इंतजार करना लगभग छोड़ दिया है। लेकिन जीवन का एक सच यह भी है कि हर अच्छी चीज तुरंत नहीं मिलती। रिश्ते समय मांगते हैं। सफलता समय मांगती है। विश्वास बनने में समय लगता है। बच्चों का व्यक्तित्व एक दिन में नहीं बनता। किसी समाज में बदलाव भी रातोंरात नहीं आता। जब हम हर चीज तुरंत पाने की मानसिकता बना लेते हैं, तो धीरे-धीरे धैर्य हमारे जीवन से बाहर होने लगता है।

इसका असर केवल व्यक्तिगत जीवन पर नहीं पड़ता। समाज में भी अधीरता बढ़ती है। लोग किसी खबर की पूरी सच्चाई जानने से पहले प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कुछ सेकंड की वीडियो देखकर राय बन जाती है। आधी जानकारी के आधार पर आरोप लगते हैं और फिर वही अधूरी जानकारी सामाजिक माध्यमों पर हजारों लोगों तक पहुंच जाती है। यानी सुविधा ने सूचना की गति तो बढ़ा दी, लेकिन समझ की गहराई जरूरी नहीं कि उसी गति से बढ़ी हो।

आज हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा विकल्प हैं, लेकिन संतुष्टि कहीं दिखाई नहीं देती। पहले एक वस्तु खरीदकर लोग वर्षों तक उसका इस्तेमाल करते थे। अब नया मॉडल आते ही पुराना बेकार लगने लगता है। कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, घर की सजावट और जीवनशैली—हर जगह लगातार कुछ नया पाने की इच्छा दिखाई देती है। बाजार हमारी इच्छाओं को सिर्फ पूरा नहीं करता, वह नई इच्छाएं भी पैदा करता है। ऐसे में सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सुविधा आखिर किसके लिए है? इंसान के लिए या इंसान सुविधा की व्यवस्था के लिए? अगर तकनीक हमें समय बचाकर देती है तो उस बचे हुए समय का उपयोग हम किस काम में कर रहे हैं? अगर मोबाइल ने काम आसान किया है तो क्या हम परिवार के साथ अधिक समय बिता रहे हैं? अगर ऑनलाइन सेवाओं ने हमें कतार से बचाया है तो क्या हमारे पास अब बातचीत, पढ़ने, सोचने और अपने लोगों के साथ बैठने के लिए ज्यादा समय है?

नई औद्योगिक क्रांति के पथ पर भारत

प्रहलाद सबनानी

भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक पांच गुना तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर एयरोस्पेस क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के चलते भारत लाभ की स्थिति में पहुंच गया है। कम लागत और कुशल इंजीनियरिंग टैलेंट भारत की महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।

भारत में आज एक नई औद्योगिक क्रांति प्रारम्भ हो चुकी है। यह विचार अमेरिका की जानी-मानी निवेश बैंकिंग संस्था जेफरीज ने व्यक्त किया है। भारत में विशेष रूप से डाटा सेंटर स्थापित करने के उद्देश्य से करोड़ों अमेरिकी डॉलर का निवेश होता दिखाई दे रहा है। डाटा सेंटर स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से टैक्स में भारी छूट भी प्रदान की जा रही है। ऐसे में भारत में डाटा सेंटर स्थापित करने की होड़ दिखाई दे रही है। पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत में डाटा सेंटरों की क्षमता दोगुनी हो चुकी है और आने वाले पांच वर्षों में इसके बढ़कर 10 जीडब्ल्यू तक पहुंचने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैश्विक स्तर पर डाटा सेंटर अब एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभर रहा है।

साथ ही, भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन इकाइयों को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए 1,300 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि निर्धारित की गई है। इसका परिणाम यह है कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए भारत में 2,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जा चुका है और यह निवेश आगे भी जारी रहने की संभावना है।

भारत आज उन चुनिंदा देशों में शामिल है, जिनके पास अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित नवीनतम तकनीक उपलब्ध है। भारत में स्पेस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक पांच गुना तक बढ़ सकती है। वैश्विक स्तर पर एयरोस्पेस क्षेत्र में मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन के चलते भारत लाभ की स्थिति में पहुंच गया है। कम लागत और कुशल इंजीनियरिंग टैलेंट भारत की महत्वपूर्ण ताकत बनकर उभरा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत अब केवल पुर्जों को जोड़कर उत्पाद तैयार करने तक सीमित नहीं है बल्कि इस क्षेत्र में उच्चस्तरीय उत्पादों का निर्माण भी करने लगा है। अगले छह वर्षों में मोबाइल कंपोनेंट्स में घरेलू वैल्यू एडिशन लगभग 20 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत तक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। सोलर क्षेत्र में भारत आज वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा सोलर पीवी उत्पादक देश बन गया है। इसका परिणाम यह है कि वर्तमान में भारत में 35 GW की सोलर क्षमता चालू है, जबकि 100 जीडब्ल्यू की क्षमता पर निर्माण कार्य चल रहा है। एशिया की सबसे बड़ी 100 कंपनियों की सूची में आज भारत की 34 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। कुल मिलाकर, पहले भारत फार्मा, टेक्सटाइल, चमड़ा उत्पाद, कृषि उत्पाद, मसाले, स्टील, ऑटोमोबाइल और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में वैश्विक स्तर पर उत्पादों का निर्यात करने में सफल हो रहा था। अब परिस्थितियां बदल रही हैं। डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर उत्पादन, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी भारत तेजी से वैश्विक

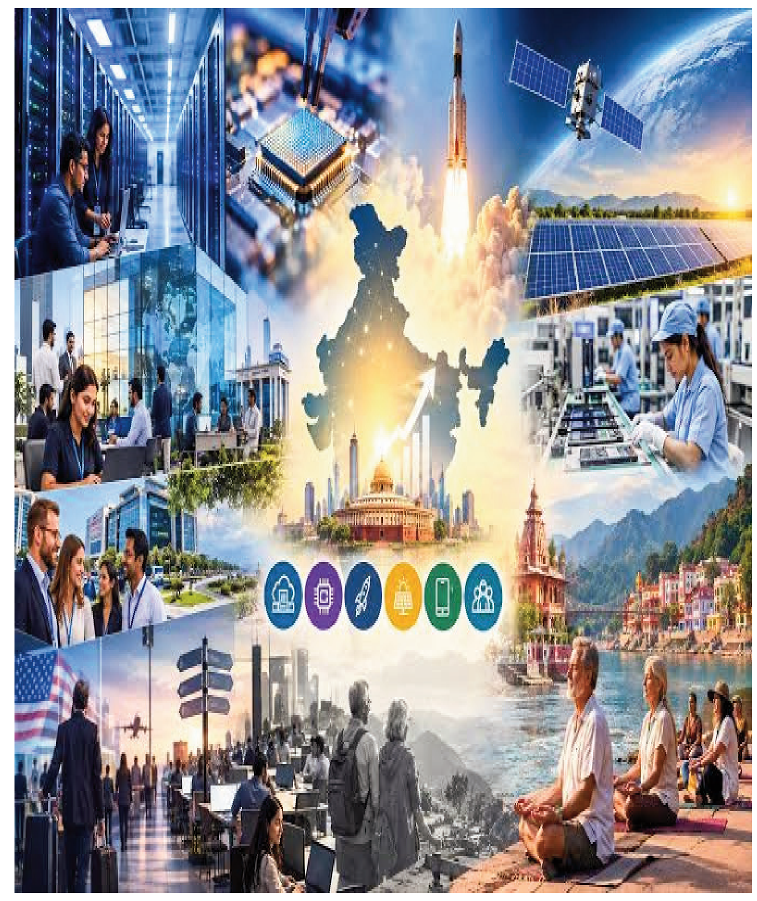

स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भारत में उपलब्ध प्रतिभा और श्रमशक्ति के भरोसे विश्व की कई बड़ी कंपनियों के बीच भारत में विशाल वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने की होड़ दिखाई दे रही है। ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने चेन्नई में एक विशाल वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा बैक-ऑफिस कार्यालय पुणे में स्थापित किया है। इस बैंक के दुनियाभर के बैक-ऑफिस संचालन में कार्यरत 11,000 कर्मचारी इस केंद्र का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।

अमेरिका के सबसे पुराने वित्तीय संस्थानों में से एक बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन ने पुणे और चेन्नई में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाली बोस्टन की एक कंपनी ने फरवरी 2026 में हैदराबाद में बड़े स्तर पर अपना अंतरराष्ट्रीय कार्यालय स्थापित किया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और पुणे में आज 1,700 से अधिक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में 19 लाख से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। भारत अब आउटसोर्सिंग हब से आगे बढ़कर उच्चस्तरीय टैलेंट सेंटर के रूप में स्थापित हो रहा है। भारत में स्थापित कुल वैश्विक योग्यता केंद्रों में लगभग 65 प्रतिशत केंद्र अमेरिकी कंपनियों द्वारा स्थापित किए गए हैं।

इन कंपनियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए जा रहे अनुसंधान का कार्य इन केंद्रों में सम्पन्न हो रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए उत्पादों का विकास भी इन्हीं केंद्रों में किया जा रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत अमेरिका की कंपनी ट्रूब्रिज ने भी फरवरी 2026 में मुंबई में वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित किया है। इस केंद्र का आने वाले समय में और विस्तार किया जाना है। इसी प्रकार बीमा, बैंकिंग, स्वास्थ्य, साइबर सिक्योरिटी, फार्मा और सुरक्षा के क्षेत्रों में कार्यरत अनेक कंपनियां भारत में अपने वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित कर रही हैं।

एक समय अमेरिका और अन्य विकसित देशों की ओर भारत से बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हुआ करता था। अब परिस्थितियों में बदलाव दिखाई दे रहा है और भारत रिवर्स ब्रेन ड्रेन की दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। विशेष रूप से अमेरिका की नीतियों के कारण अन्य देशों से अमेरिका जाने वाले टैलेंट के लिए वहां लंबे समय तक रहना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिका और अन्य यूरोपीय देशों में जनसंख्या संबंधी परिस्थितियां भी बदल रही हैं। इन देशों में जन्म दर लगातार कम हो रही है। वहां जीवनशैली तेजी से व्यक्तिगत केंद्रित होती जा रही है। विवाह जैसी सामाजिक संस्था के प्रति दृष्टिकोण में भी व्यापक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। पश्चिमी देशों में लिव-इन रिलेशनशिप का चलन बढ़ा है और विवाह को लेकर पारंपरिक सोच में बदलाव आया है। तलाक की दरों में भी कई देशों में वृद्धि दर्ज की गई है।

इन देशों में सामान्य जीवन-यापन की लागत लगातार बढ़ रही है। परिवार बढ़ाने और बच्चों के पालन-पोषण पर होने वाला खर्च भी लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। इसी संदर्भ में 'डबल इनकम नो किड्स' यानी DINK का विचार भी जोर पकड़ रहा है। इसका अर्थ है कि परिवार में दोनों व्यक्ति आय अर्जित करें, पर बच्चे न हों।

भारतीय दर्शन में विवाह को परिवार, समाज और अगली पीढ़ी के निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में देखा गया है। इसके विपरीत, पश्चिमी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सुख को अधिक महत्व दिए जाने के कारण पारिवारिक संरचनाओं में बदलाव दिखाई दे रहा है। पुनर्जन्म और जीवन के आध्यात्मिक उद्देश्य को लेकर भारतीय तथा पश्चिमी दार्शनिक दृष्टिकोणों में भी महत्वपूर्ण अंतर है।

पश्चिमी समाज में बढ़ती भौतिक आवश्यकताओं, जीवन-यापन की लागत और व्यक्तिगत जीवनशैली का प्रभाव परिवार एवं जनसंख्या संरचना पर दिखाई दे रहा है। नागरिकों के सामने यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि वे अपनी आय और संसाधनों का कितना हिस्सा परिवार तथा बच्चों के पालन-पोषण पर खर्च कर सकते हैं। परिणामस्वरूप कई देशों में परिवार का आकार छोटा होता जा रहा है और जन्म दर में गिरावट देखी जा रही है।

आज पश्चिमी देशों के नागरिक, विशेष रूप से प्रौढ़ नागरिक, अपने जीवन के अंतिम चरण को अधिक सहज और शांतिपूर्ण बनाने के उद्देश्य से भारत की ओर भी आकर्षित हो रहे हैं। भारत की आध्यात्मिक नगरी ऋषिकेश, हरिद्वार तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अनेक क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की उपस्थिति बढ़ी है। कुछ देशों के नागरिक गोवा जैसे राज्यों में भी आकर बस रहे हैं।

भारत के इन स्थलों पर उन्हें मानसिक शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त होता है। प्रारम्भ में अनेक विदेशी नागरिक योग और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत आते हैं। भारत में रहने के दौरान उन्हें यहां की जीवनशैली और आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव होता है। इसके बाद कुछ लोग भारत में ही लंबे समय तक रहने या बसने का निर्णय लेते हैं।

भारत में तेजी से विकसित हो रही औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं के साथ-साथ यहां की विशाल प्रतिभा, कुशल इंजीनियरिंग क्षमता, अपेक्षाकृत कम लागत और आध्यात्मिक-सांस्कृतिक वातावरण भी वैश्विक स्तर पर भारत के आकर्षण को बढ़ा रहा है। डाटा सेंटर से लेकर सेमीकंडक्टर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक योग्यता केंद्रों तक अनेक क्षेत्रों में भारत का विस्तार इस बात का संकेत है कि देश एक नए औद्योगिक और तकनीकी चरण में प्रवेश कर रहा है।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

ट्रंप का मीडिया से महायुद्ध!

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता और स्वतंत्र पत्रकारिता के बीच संबंध केवल समाचार देने और लेने तक सीमित नहीं होता,बल्कि यह नागरिकों के सूचना के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शासन की जवाबदेही से सीधे जुड़ा होता है।भारत सहित अनेक लोकतांत्रिक देशों में समाचार माध्यमों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है

वैश्विक पटल पर लोकतंत्र, मानवाधिकार और सूचना के अधिकार का अटूट संबंध अंतरराष्ट्रीय समाज में मानवाधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण किसी भी सभ्य राष्ट्र की पहली पहचान माना जाता है।संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत सार्वभौमिक घोषणापत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति, विचार और बिना किसी डर के सूचना प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को जमीन पर उतारने का सबसे बड़ा जिम्मा सूचना तंत्र और समाचार माध्यमों के कंधों पर होता है। जब तक नागरिकों तक निष्पक्ष पारदर्शी और सटीक जानकारियां नहीं पहुंचेंगी, तब तक वे अपने अधिकारों के प्रति न तो सजग हो सकते हैं और न ही किसी दमनकारी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। यही कारण है कि स्वतंत्र जनसंचार को किसी भी लोकतांत्रिक देश का चौथा स्तंभ स्वीकार किया गया है, जो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के समानांतर समाज में संतुलन और शुचिता बनाए रखने का काम करता है। वैश्विक स्तर पर जब भी शासन प्रशासन द्वारा सूचना तंत्र को नियंत्रित करने या उसकी आवाज दबाने का प्रयास किया जाता है, तो वह सीधे तौर पर आम जनता के मौलिक अधिकारों पर आघात होता है। इसी अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि में वर्तमान परिदृश्य में अमेरिका जैसे सबसे पुराने लोकतंत्र में सरकार और मुख्यधारा के समाचार माध्यमों के बीच उपजा महायुद्ध इस बात का ज्वलंत उदाहरण है।अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रमुख समाचार संस्थानों के बीच सितंबर 2026 में पैदा हुआ विवाद पूरी दुनियाँ का ध्यान खींच रहा है।उपलब्ध ताजा सूचनाओं के अनुसार 18 सितंबर को ट्रंप ने सीएनएन एमएस नाउ और पोलिटिको को व्हाइट हाउस से प्रतिबंधित करने की घोषणा की और उन पर ऐसी खबरें प्रकाशित करने का आरोप लगाया जिन्हें वे झूठी या मनगढ़ंत मानते हैं।इसके बाद 19 सितंबर को इन संस्थानों के पत्रकारों को व्हाइट हाउस में प्रवेश से रोका गया और उनके प्रवेश-पत्र निष्क्रिय किए गए।यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह केवल सामान्य समाचार- विवाद नहीं रहा; मामला अब सीधे संवैधानिक अधिकारों और सरकारी प्रेस-पहुंच के प्रश्न में बदल चुका है।यह आर्टिकल मीडिया में आई जानकारी के अनुसार बनाया गया है।

विवाद का अगला महत्वपूर्ण चरण 21 सितंबर को सामने आया,जब राष्ट्रपति के समाचार-संग्रह के लिए काम करने वाले प्रमुख दूरदर्शन समाचार समूहों की साझा व्यवस्था रुक गई।इस व्यवस्था में एबीसी,सीबीएस सीएनएन, फॉक्स और एनबीसी बारी-बारी से राष्ट्रपति के कार्यक्रमों की दृश्य सामग्री तैयार करके अन्य समाचार संस्थानों को उपलब्ध कराते हैं।सीएनएन पहले ही प्रतिबंधित था,जबकि शेष प्रमुख समूहों ने साझा समाचार -सामग्री उपलब्ध कराने वाली इस व्यवस्था को रोक दिया।इसलिए इसे शाब्दिक अर्थ में पांचों संस्थानों द्वारा समान प्रकार का बहिष्कार कहना पूरी तरह सटीक नहीं होगा;अधिक सही स्थिति यह है कि सीएनएन पर सरकारी प्रतिबंध के बाद साझा दूरदर्शन समाचार व्यवस्था ही ठप हो गई।इस घटनाक्रम का महत्व इसलिए बढ़ गया क्योंकि राष्ट्रपति के विदेश और देश के भीतर होने वाले कार्यक्रमों की प्रत्यक्ष समाचार-सामग्री उपलब्ध कराने की पारंपरिक व्यवस्था प्रभावित हुई।

इसी बीच व्हाइट हाउस ने 21 सितंबर को "ट्रंप टीवी : द एसेंशियल्स स्टेशन" नाम से चौबीसों घंटे चलने वाला डिजिटल प्रसारण मंच शुरू किया। आधिकारिक व्हाइट हाउस अभिलेख में इसके आरंभ की तारीख 21 सितंबर दर्ज है।यह पारंपरिक दूरदर्शन चैनल की बजाय इंटरनेट आधारित प्रसारण व्यवस्था है,जिसमें राष्ट्रपति के भाषणों,प्रशासनिक कार्यक्रमों घोषणाओं और पुराने महत्वपूर्ण दृश्यों को सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है।समाचार रिपोर्टों के अनुसार इसमें ट्रंप के पुरानेभाषणों और प्रशासन से जुड़े कार्यक्रमों की सामग्री दिखाई गई है।इसका मूल महत्व यह है कि जब स्वतंत्र समाचार संस्थानों और सरकार के बीच प्रत्यक्ष संवाद का रास्ता बाधित हुआ, तब सरकार ने जनता तक अपनी सामग्री पहुंचाने के लिए सटीकता से अपना सीधा माध्यम खड़ा कर दिया।

यहीं से विवाद का सबसे गंभीर लोकतांत्रिक प्रश्न सामने आता है,क्या सरकार आलोचनात्मक पत्रकारिता से असहमति के आधार पर किसी समाचार संस्थान की पहुंच रोक सकती है?अमेरिकी संविधान के प्रथम संशोधन में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को विशेष संरक्षण प्राप्त है। हालांकि व्हाइट हाउस का तर्क है कि राष्ट्रपति भवन में प्रवेश कोई पूर्ण अधिकार नहीं बल्कि प्रशासन द्वारा नियंत्रित सुविधा है और सरकार को सुरक्षा तथा प्रशासनिक कारणों से पहुंच नियंत्रित करने का अधिकार है। दूसरी ओर प्रतिबंधित समाचार संस्थानों का कहना है कि उनकी पहुंच उनके समाचारों की विषयवस्तु के कारण छीनी गई और यह प्रथम संशोधन तथा उचित कानूनी प्रक्रिया के अधिकार का उल्लंघन है। 23 सितंबर 2026 को संघीय न्यायालय में इसी विवाद पर तत्काल राहत संबंधी सुनवाई निर्धारित की गई है। कानूनी दृष्टि से संभावित न्यायिक निर्णय कई बातों पर निर्भर करेगा। न्यायालय यह देख सकता है कि व्हाइट हाउस ने प्रवेश प्रतिबंध लगाने के लिए कोई स्पष्ट, समान और विषय- वस्तु से स्वतंत्र नियम लागू किया था या प्रतिबंध आलोचनात्मक समाचारों के कारण लगाया गया।न्यायालय यह भी देख सकता है कि पत्रकारों के प्रवेश- पत्र अचानक निष्क्रिय करने से उचित कानूनी प्रक्रिया के अधिकार प्रभावित हुए या नहीं। विशेष रूप से महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि जिस स्थान को सरकार ने सामान्य समाचार -संग्रह के लिए प्रेस के लिए खोला है, वहां किसी संस्थान को उसके विचार या समाचार -सामग्री के आधार पर अलग करना संवैधानिक रूप से कितना उचित है। पूर्व में न्यायालयों ने प्रेस-पहुंच से जुड़े मामलों में यह अंतर किया है कि सीमित, सुरक्षा-आधारित स्थानों पर सरकार का नियंत्रण अधिक हो सकता है,लेकिन सामान्य रूप से खुले प्रेस क्षेत्र में विचार के आधार पर भेदभाव अलग संवैधानिक प्रश्न पैदा करता है। इस मामले में न्यायालय के सामने दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह भी होगा कि क्या सरकार का दावा कि समाचार संस्थान गलत सूचना फैला रहे थे,किसी ठोस और कानूनन मान्य आधार से समर्थित है। केवल किसी समाचार की आलोचना या उससे राजनीतिक असहमति और वास्तविक सुरक्षा- जोखिम दो अलग- अलग कानूनी परिस्थितियां हैं। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों में भी अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध के लिए कानून, वैध उद्देश्य, आवश्यकता और अनुपातिकता की कसौटियां महत्वपूर्ण मानी गई हैं।

पितरों के प्रति कर्तव्य : स्मृति से संस्कार तक

मनुष्य कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, उसकी जड़ें अपने परिवार, समाज, संस्कृति और पूर्वजों से जुड़ी रहती हैं। वर्तमान का व्यक्तित्व अतीत की अनेक पीढ़ियों के अनुभव, संघर्ष, संस्कार और त्याग से निर्मित होता है। हम जिस परिवार, नाम, संस्कार और सामाजिक पहचान के साथ जीवन जीते हैं, उसके पीछे हमारे माता-पिता और पूर्वजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए पितरों का स्मरण केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व की जड़ों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी है।

भारतीय संस्कृति में पितृ-स्मरण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मों के माध्यम से पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त की जाती है। इन परंपराओं का बाहरी स्वरूप चाहे धार्मिक हो, लेकिन उनका मूल भाव स्मरण, कृतज्ञता, श्रद्धा और अपने पूर्वजों के प्रति ऋण स्वीकार करने में निहित है। यह भाव मनुष्य को अहंकार से दूर करता है और उसे यह याद दिलाता है कि जीवन की यात्रा में वह अकेला नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने समय की परिस्थितियों में संघर्ष किया, परिवार को संभाला, अभावों से जूझे और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन की नींव रखी। उनकी सबसे बड़ी विरासत केवल जमीन-जायदाद या भौतिक संपत्ति नहीं थी। उनका वास्तविक धन था—ईमानदारी, परिश्रम, त्याग, अनुशासन, सहनशीलता, करुणा और परिवार के प्रति जिम्मेदारी।

इसीलिए पितरों के प्रति कर्तव्य को केवल कर्मकांड तक सीमित करना उचित नहीं होगा। यदि हम श्रद्धा से उनका स्मरण करते हैं, तो उनके श्रेष्ठ मूल्यों को अपने जीवन में अपनाना भी हमारी जिम्मेदारी है। पितृ-स्मरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि हम अपने जीवित माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। किसी दिवंगत पूर्वज के लिए श्रद्धा व्यक्त करना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उसी परिवार में जीवित माता-पिता अकेलेपन, उपेक्षा या भावनात्मक दूरी का अनुभव करें, तो हमें अपने व्यवहार पर भी विचार करना चाहिए। आज संयुक्त परिवारों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। रोजगार, शिक्षा और बेहतर अवसरों की तलाश में परिवार अलग-अलग शहरों और देशों में बस रहे हैं। इसका एक सकारात्मक पक्ष है कि लोगों को नए अवसर मिलते हैं, लेकिन दूसरी ओर बुजुर्गों के अकेलेपन की समस्या भी सामने आती है। कई बार उनके पास आर्थिक सुविधाएँ होती हैं, परंतु भावनात्मक साथ नहीं होता। बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता सम्मान, संवाद और अपनत्व की होती है। उनके साथ कुछ समय बैठना, उनकी बात ध्यान से सुनना, उनके अनुभवों का सम्मान करना और आवश्यकता पड़ने पर उनका सहारा बनना किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से कम महत्वपूर्ण नहीं है। जिस घर में जीवित माता-पिता सम्मानित होते हैं, वही घर वास्तव में पितृ-संस्कारों का सम्मान करता है। पितृ-ऋण कोई ऐसा ऋण नहीं जिसे धन से चुकाया जा सके। यह एक भावनात्मक और नैतिक जिम्मेदारी है। इसे चुकाने का अर्थ है—पूर्वजों से मिले अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाना और परिवार तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना। यदि हमारे पूर्वजों ने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा को महत्व दिया, तो हमें अगली पीढ़ी की शिक्षा के लिए गंभीर होना चाहिए। यदि उन्होंने जरूरतमंदों की मदद की, तो हमें भी अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद का सहारा बनना चाहिए। यदि उन्होंने ईमानदारी से जीवन जिया, तो हमें भी कठिन परिस्थितियों में ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह पितरों की स्मृति हमारे आचरण में दिखाई देने लगती है। आज बच्चों और युवाओं का अधिकांश समय डिजिटल संसार में बीत रहा है। उन्हें विश्व की जानकारी तो तत्काल मिल जाती है, लेकिन कभी-कभी अपने ही परिवार के इतिहास और पूर्वजों के जीवन-संघर्ष से वे अनजान रह जाते हैं। यह परिवार की जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को बताया जाए कि उनके दादा-दादी, नाना-नानी और अन्य पूर्वजों ने किस प्रकार जीवन जिया। उनके संघर्षों और उपलब्धियों की कहानियाँ बच्चों में आत्मविश्वास, कृतज्ञता और संस्कार पैदा कर सकती हैं। परिवार के बुजुर्गों के संस्मरण सुनना, पुरानी तस्वीरों को सुरक्षित रखना और परिवार की सकारात्मक परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाना भी पितृ-स्मरण का एक सुंदर रूप हो सकता है।

जम्मू भाजपा ने की राहुल और कांग्रेस से मांगी बिना शर्त माफी की मांग

जम्मू, एजेंसी।

जम्मू-कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सत शर्मा ने कांग्रेस नीत विपक्ष पर आरोप लगाया है कि उसने चुनाव आयोग के खिलाफ झूठा अभियान चलाया और एक संवैधानिक संस्था को दलीय राजनीति में घसीटा है, इसलिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। रविवार को पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि चुनावों या अन्य राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिशों को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उनके साथ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील सेठी और प्रवक्ता अरुण गुप्ता भी मौजूद थे। शर्मा ने कहा कि चुनाव आयोग के संयुक्त स्पष्टीकरण ने चुनाव आयुक्तों के बीच कथित मतभेदों को लेकर कांग्रेस के बनाए जा रहे झूठे प्रचार की हवा निकाल दी है।

उन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ-साथ चुनाव आयुक्त डॉ. एस. एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी ने सामूहिक रूप से स्पष्ट किया है कि विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित निर्णय पूर्ण आयोग के अनुमोदन से लिए गए थे।

यूपी के विकास की गूंज अब दुनिया में सुनाई दे रही: गोयल

नोएडा, एजेंसी।

उत्तर प्रदेश अब विकास और निवेश के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बना रहा है और प्रदेश के विकास की गूंज देश ही नहीं, दुनिया में भी सुनाई दे रही है। यह बात केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित चौथे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (यूपीआईटीएस) के तीसरे दिन कही।

गोयल ने 'लीवरेजिंग इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ' विषय पर आयोजित विशेष बिजनेस सेशन में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई यात्रा तय की है।

उद्यमियों का बढ़ता भरोसा, निवेश के नए अवसर और आधुनिक उद्योगों का विस्तार प्रदेश की बदलती तस्वीर को सामने रख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, बड़े औद्योगिक पार्क और डिफेंस, सेमीकंडक्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में निवेश हो रहा है। नोएडा के निकट विकसित हो रही रोबोटिक्स फैक्ट्री का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अब भविष्य के उद्योगों में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है।

उन्होंने कहा कि विकास की अगली मंजिल अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निर्यात, विदेशी निवेश और पर्यटन से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश के स्थानीय

उत्पाद और ब्रांड अब वैश्विक बाजारों में पहचान बना रहे हैं।सरकार ने वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश के निर्यात को पांच लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य प्रदेश की बढ़ती आर्थिक क्षमता और उद्यमियों के बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है। उन्होंने 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश के कारोबारी माहौल का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय कानून-व्यवस्था और निवेश के वातावरण को लेकर उद्यमियों में चिंता रहती थी।

उनके अनुसार बड़े उद्योगों की स्थापना को लेकर पर्याप्त उत्साह नहीं था और भ्रष्टाचार तथा कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं के कारण व्यापार जगत में निराशा का माहौल था। उस समय पलायन की चर्चा आम थी और उत्तर प्रदेश को पिछड़े राज्यों में गिना जाता था। ऐसे माहौल में रोबोटिक्स, डिफेंस कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश की कल्पना करना मुश्किल था। केंद्रीय मंत्री ने 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र की तैयारी का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों से सुझाव लिए थे। युवाओं, महिलाओं और समाज के विभिन्न वर्गों की आकांक्षाओं को संकलित कर संकल्प पत्र तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बड़े वित्तीय संसाधनों की जरूरत थी। सीमित बजट के बावजूद विकास की रफ्तार बनाए रखने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने पर जोर दिया गया। उत्तर प्रदेश ने विकास के साथ राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय प्रगति की है।

उन्होंने दावा किया कि 2016-17 की तुलना में प्रदेश के आबकारी राजस्व में करीब पांच गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने भूमि हस्तांतरण, रजिस्ट्रेशन फीस और स्टांप ड्यूटी से मिलने वाली आय का उल्लेख करते हुए कहा कि संसाधन वही रहे, लेकिन व्यवस्था में सुधार से राजस्व संग्रह में बड़ा बदलाव आया। खनन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 2016-17 में बालू, मौरंग, पत्थर और अन्य खनिजों से करीब 1,548 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ था।

मतदाता सूची में नियमित रूप से बदलाव जरूरी: फडणवीस

नागपुर, एजेंसी।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का बचाव करते हुए कहा कि वर्ष 2000 के बाद से मतदाता सूचियों का उचित तरीके से पुनरीक्षण नहीं किया गया है और आदर्श रूप से हर पांच साल में इन्हें अद्यतन किया जाना चाहिए। फडणवीस ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर लोगों के शहरों की ओर पलायन के कारण ग्रामीण महाराष्ट्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में एसआईआर की जरूरत अधिक महसूस होती है। उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनावी पुनरीक्षण प्रक्रिया पर सवाल उठाने की बजाय आत्ममंथन करने का आग्रह किया।

नागपुर लोकसभा क्षेत्र सहित कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में एसआईआर के कारण मतदाताओं की संख्या में कमी आने के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री फडणवीस ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण के बाद जिन 15 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में काफी कमी आई थी, वहां भी तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार निर्वाचित हुए।

उन्होंने कहा, अगर कथित तौर पर भाजपा के मतदाता नहीं होने के कारण मतदाताओं के नाम हटाए गए थे, तो इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार कैसे जीत गये?

फडणवीस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से संवैधानिक संस्थाओं को लेकर की गयी टिप्पणियों की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि गांधी बार-बार ऐसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं और लोगों का उन पर विश्वास कम करने की कोशिश करते हैं।

मुख्यमंत्री ने गांधी की राजनीतिक सोच को 'अति वामपंथी' बताते हुए आरोप लगाया कि संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों के विश्वास को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद का जिक्र करते हुए फडणवीस ने कहा कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने स्पष्ट किया था कि यह प्रक्रिया सर्वसम्मति से शुरू की गई थी और उनके बीच कोई मतभेद नहीं था। उन्होंने मतदाता पंजीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म-6 को लेकर पैदा हुए भ्रम को भी खारिज किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित प्रारूप में इस फॉर्म की वैधता को बरकरार रखा है।

28 सितंबर को लुधियाना में 'जश्न-ए-इंकलाब'

लुधियाना,एजेंसी। पंजाब आम आदमी पार्टी (आप) के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने रविवार को राज्य के लोगों से 28 सितंबर को पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पीएयू) मैदान में आयोजित होने वाले 'जश्न-ए-इंकलाब' कार्यक्रम में परिवार सहित शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती के साथ पंजाब की संस्कृति, संगीत और शहीदों की विरासत को समर्पित होगा।

पन्नू ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कार्यक्रम अपराह्न तीन बजे शुरू होगा। इसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, मंत्री, विधायक और प्रदेशभर से लोग शामिल होंगे।

कर्नाटक में एसआईआर की लड़ाई मतदान केंद्रों तक पहुंची

बेंगलुरु, एजेंसी।

कर्नाटक में मतदाता सूची से जुड़ी लड़ाई अब मतदान केंद्रों तक पहुंचाने की तैयारी है और इसी सिलसिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने संकेत दिये हैं कि पार्टी चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया के खिलाफ अपने विरोध को केवल राजनीतिक बयानों तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ जारी अभियान को जमीनी आंदोलन में बदलेगी। हरिप्रसाद ने यहां कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि मतदाता सूची के संशोधन की आड़ में भाजपा अपनी बिहार वाली चाल कर्नाटक में नहीं दोहरा सकती। उन्होंने कहा कि

मतदाता सूची से काटे गये नामों की जमीनी स्तर पर पड़ताल कांग्रेस करेगी और यह तय करेगी कि सभी योग्य मतदाताओं के नाम सूची में बरकरार रहें।

हरिप्रसाद ने कहा, बिहार में जो भी रणनीति अपनायी गयी थी, उसे कर्नाटक में नहीं दोहराया जा सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के लोग अपने मताधिकार को छिनने नहीं देंगे।

ग्रामीण, शहरी स्कूलों की गुणवत्ता का अंतर हुआ कम: साहा

अगरतला, एजेंसी।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की गुणवत्ता के अंतर को कम करने में राज्य सरकार की सफलता की सराहना की है। डॉ. साहा ने रविवार को कहा कि यह उपलब्धि सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के कारण संभव हुई है। उन्होंने बताया कि राज्य में 213 स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1,178 करोड़ रुपये का पर्याप्त प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य आधुनिक तकनीक के माध्यम से वंचित क्षेत्रों तक शिक्षा के अवसर पहुंचाना है।

पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मूल्य-आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। पंडित विद्यासागर देश के प्रमुख शिक्षाविद और समाज सुधारक थे।उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक प्रगति के साथ संरक्षित रखने के लिए लगातार समर्थन दिया है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी परिलक्षित होता है।

बीएलए कांग्रेस के असली स्तंभ: विक्रमार्का

खम्मम,एजेंसी। तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) कांग्रेस के असली स्तंभ हैं और भरोसा दिलाया कि पार्टी और सरकार दोनों ही ज़मीनी स्तर पर काम करने वालों के साथ खड़ी रहेंगी।

भट्टी ने रविवार को नागुलवंचा गांव में चिंताकानी मंडल के कांग्रेस बीएलए की बैठक को संबोधित करते हुए उनसे सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने और लोगों की सरकार की साख को मजबूत करने में मदद करने का आग्रह किया।

उन्होंने चिंताकानी बीएलए के काम की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे मंडलों के मुकाबले उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है।

पर्यटन का रूप बदलने के लिए केरलम एआई करेगा इस्तेमाल: विष्णुनाथ

तिरुवनंतपुरम,एजेंसी।

केरलम अपने पर्यटन क्षेत्र को बदलने और सहज, समावेशी एवं टिकाऊ यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तथा अत्याधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल करेगा। पर्यटन, संस्कृति और सिनेमा मंत्री पीसी विष्णुनाथ ने विश्व पर्यटन दिवस 2026 के अवसर पर दिये संदेश में कहा कि पर्यटकों की बदलती मांगों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए केरलम ने पहले ही अपने पर्यटन क्षेत्र को एआई और डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से जोड़ना शुरू कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष की थीम ₹पर्यटन को पुनर्गठित करने के लिए डिजिटल एजेंडा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता₹ है।

उन्होंने कहा कि वैश्विक ब्रांड के रूप में स्थापित 'केरलम पर्यटन' ने राज्य को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर डिजिटल प्लेटफॉर्म तक, लगातार नवीन संचार माध्यमों को अपनाया है।

विष्णुनाथ ने कहा, पर्यटकों को विविध सौगात देने का वादा करते हुए केरलम एक अंतरराष्ट्रीय अनुभवात्मक गंतव्य के रूप में उभरने की अपनी अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए पर्यटन क्षेत्र को नया आकार दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य अलग-अलग स्थानों पर केंद्रित पैकेजों के माध्यम से केवल व्यक्तिगत स्थलों और उत्पादों का प्रचार करने के बजाय पर्यटकों को पूरे केरलम का समग्र अनुभव प्रदान करना है।

इस एकीकृत पर्यटन अनुभव को प्राप्त करने में बाधा रहित संचार और सूचना तथा सेवाओं तक आसान पहुंच महत्वपूर्ण होगी। नयी प्रौद्योगिकियां बुकिंग और भुगतान से लेकर अतिथि संबंधों तक, यात्रा और आतिथ्य सेवाओं की पूरी शृंखला को अधिक सुविधाजनक बना सकती हैं। मंत्री ने कहा कि पर्यटन विभाग ने हितधारकों के सहयोग से पहले ही उन तरीकों की तलाश शुरू कर दी है, जिनसे एआई पर्यटन क्षेत्र को अधिक स्मार्ट, समावेशी और टिकाऊ बना सकता है। उन्होंने कहा, यह अत्यधिक प्रतिस्पर्धी घरेलू और वैश्विक परिदृश्य में राज्य की पर्यटन गतिविधियों को गति और विस्तार प्रदान करेगा।

चुनाव आयोग के बयान से कांग्रेस के आरोप बेनकाब: चुघ

चंडीगढ़, एजेंसी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय मुख्यालय प्रभारी एवं सांसद तरुण चुघ ने रविवार को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस और लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पूर्ण चुनाव आयोग की बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान ने कांग्रेस के दावों की स्थिति स्पष्ट कर दी है।

चुघ ने कहा कि 26 सितंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार तथा चुनाव आयुक्त डॉ. एस.एस. संधू और डॉ. विवेक जोशी की पूर्ण बैठक हुई।

इसके बाद आयोग ने स्पष्ट किया

कि 24 जून 2025 को जारी एसआईआर का मूल आदेश और इसके विभिन्न चरणों की समय-सारणी पूरे आयोग की सर्वसम्मति से मंजूर हुई थी। उन्होंने कहा कि आयोग ने 27 मई 2026 के उच्चतम न्यायालय के आदेश का भी संज्ञान लिया है। उन्होंने कैबिनेट सचिव को भेजे गये पत्र को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि आयोग के अनुसार यह पत्र एसआईआर या किसी नीतिगत विषय से संबंधित नहीं था, बल्कि प्रतिनियुक्ति पर आये एक अधिकारी के प्रशासनिक कार्य से जुड़ा था।

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित अधिकारी के कार्य-वितरण से जुड़ा आदेश दो चुनाव आयुक्तों के निर्देश के बाद लागू नहीं किया गया और सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी जारी रही।

चुघ ने कहा कि कांग्रेस ने जिस प्रशासनिक पत्र को एसआईआर और आयोग की कार्यप्रणाली से जोड़कर मुद्दा बनाया, आयोग के अनुसार उसका इनसे संबंध नहीं था। उन्होंने कांग्रेस से तथ्यों के आधार पर राजनीतिक सवाल उठाने की अपील की। उन्होंने मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 को लेकर भी कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया।

दलित-आदिवासी समस्या पर बुधवार को होगी कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक

नई दिल्ली,एजेंसी। कांग्रेस दलित तथा आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों और उनकी विभिन्न समस्याओं पर विचार के लिए 29 सितंबर को यहां महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करेगी। कांग्रेस सांसद डॉ. मल्लू रवि, मनोज कुमार, तनुज पूनिया, करमवीर बौद्ध, हमदुल्लाह सईद, भजन लाल जाटव तथा आदिवासी कांग्रेस की प्रमुख विक्रांत भूरिया ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में कांग्रेस के लोकसभा एवं राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री, विधायक और देशभर से पार्टी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

चुनाव आयोग के कामकाज की जांच हो और ज्ञानेश कुमार पद छोड़ें: चव्हाण

कोल्हापुर, एजेंसी।

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने रविवार को चुनाव आयोग के कामकाज की गहन जांच और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस रिपोर्ट को ₹चौंकाने वाला₹ करार दिया और कहा कि चुनाव आयोग के कामकाज को लेकर लगाए गए आरोपों की विस्तृत जांच होनी चाहिए।चव्हाण ने कहा कि चुनाव आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है।

उन्होंने उच्चतम न्यायालय के 1995 के ऐतिहासिक निर्णय (टी.एन. शेषन बनाम भारत सरकार) का संदर्भ दिया, जिसमें चुनाव आयोग की शक्तियों, भूमिका और कामकाज के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया था। चव्हाण ने आरोप लगाया कि श्री कुमार ने अन्य सदस्यों से परामर्श किए बिना आयोग की ओर से निर्णय लिए हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया रिपोर्ट में इन विवरणों को दर्ज किया गया है और दावा किया कि इन गंभीर आरोपों का अब तक कोई खंडन नहीं किया गया है।

सार समाचार

त्रिपुरा में कड़ी सुरक्षा के होगा एडीसी का वीसी चुनाव

अगरतला,एजेंसी। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (एडीसी) के तहत ग्राम समितियों (वीसी) के चुनाव कराने की तैयारियां पूरी कर ली गयी हैं। ये चुनाव सोमवार को 44 प्रखंडों के 1,095 मतदान केंद्रों पर होंगे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच करीब 6.65 लाख मतदाताओं के मतदान में हिस्सा लेने की उम्मीद है।ग्राम समिति चुनाव उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद एक दशक में पहली बार हो रहे हैं। इससे पहले ग्राम समिति के चुनाव 2016 में हुए थे और उसके बाद अब तक चुनाव नहीं कराए गये थे। विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के कुल 8,176 प्रत्याशी 4,597 ग्राम समिति पदों के लिए चुनाव लड़ रहे हैं।

माकपा ने मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग दोहरायी

नई दिल्ली,एजेंसी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने रविवार को चुनाव आयोग की आलोचना करते हुए कहा कि चुनाव आयोग के 26 सितंबर के जवाब में आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के चल रहे 'विशेष गहन पुनरीक्षण ' (एसआईआर) से जुड़े गंभीर सवालों का समाधान नहीं किया गया है। इसके साथ ही पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के तुरंत इस्तीफ़े की अपनी मांग भी दोहराई है। माकपा पोलित ब्यूरो द्वारा जारी एक बयान में पार्टी ने कहा कि चुनाव आयोग का जवाब तीन-सदस्यीय आयोग के कामकाज के बारे में हुए खुलासों से पैदा हुई चिंताओं का ठीक से समाधान नहीं करता है-खासकर मतदाता पंजीकरण और नाम हटाने, मतदाता डेटाबेस तक पहुँच और मतदाता सूची से जुड़ी प्रक्रियाओं में बदलाव के मामलों में।

पोलित ब्यूरो ने कहा, ईसीआई) द्वारा 26 सितंबर को जारी बयान में आयोग के कामकाज और मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण ' (एसआईआर) के बारे में हुए खुलासों से उठे गंभीर सवालों का समाधान नहीं किया गया है। बयान में माकपा 'द इंडियन एक्सप्रेस' की एक जांच का ज़िक्र कर रही थी। रिपोर्ट के अनुसार श्री जोशी ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए ज़रूरी आवेदन 'फॉर्म 6' में प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जताई थी।

संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों पर बात करे कांग्रेस: धामी

देहरादून, एजेंसी।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को कहा कि कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर भ्रम फैलाने के बजाय तथ्यों पर बात करें। धामी ने अपने आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आनन फानन आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पहली बार विपक्षी कांग्रेस और उसके आरोपों पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारत के मजबूत लोकतंत्र का आधार देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं और चुनाव आयोग भी देश की स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियों पर आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं संवैधानिक विषयों को राजनीतिक ढाल बनाकर जनता के बीच भ्रम पैदा करने से कांग्रेस की समस्याओं का समाधान नहीं होगा।

धामी ने कहा कि आज की पीढ़ी जागरूक है और वह तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय करना जानती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी ने देहरादून में दावा किया कि भाजपा सरकार ने नकल के मामलों में किसी माफिया को जेल नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नकल माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई की गई है और सरकार के अनुसार 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि भर्ती परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है।

पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

राज्य में 27 लाख नाम हटाए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया

शुभेंदु ने एसआईआर को लेकर निर्वाचन आयोग का बचाव किया

कोलकाता,एजेंसी।

पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच निर्वाचन आयोग का बचाव किया और राज्य में 27 लाख नाम हटाए जाने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नामों को हटाए जाने के लिए न तो भाजपा और न ही निर्वाचन आयोग को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अधिकारी ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी के बीच हुई बैठक और उसके बाद निर्वाचन आयोग की ओर से जारी बयान का भी हवाला दिया।

उन्होंने इस आरोप को खारिज किया कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर से जुड़े फैसले सीईसी ने एकतरफा तरीके से लिए थे। उन्होंने कहा कि तीनों निर्वाचन आयुक्तों की बैठक से स्पष्ट होता है कि ये फैसले सर्वसम्मति से लिए गए थे।

अधिकारी ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, 27 लाख नाम हटाए जाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है, भारतीय जनता पार्टी या निर्वाचन आयोग की नहीं। उनके द्वारा दायर एक मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के बाद न्यायिक अधिकारियों ने यह फैसला लिया था।

अधिकारी का यह बयान बनर्जी द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर

अपना हमला तेज किए जाने के एक दिन बाद आया। बनर्जी ने आरोप लगाया था कि एसआईआर का इस्तेमाल भाजपा को बंगाल पर कब्जा करने में मदद करने के लिए किया गया और उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग की थी। इस पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा, तीनों निर्वाचन आयुक्तों की बैठक और उसके बाद जारी बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि एसआईआर से जुड़े फैसले किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिए थे।

वह 26 सितंबर को नयी दिल्ली स्थित निर्वाचन सदन में हुई बैठक का जिक्र कर रहे थे। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को कहा कि एसआईआर से संबंधित सभी आदेशों को तीनों निर्वाचन आयुक्तों की सर्वसम्मत मंजूरी मिली थी और मतदाता पंजीकरण के लिए फॉर्म-6 में किए गए बदलावों को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था। आयोग ने यह स्पष्टीकरण निर्वाचन आयोग में फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर जारी विवाद और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की चिंताओं के बीच दिया।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो निर्वाचन आयुक्तों के बीच मतभेद होने की खबरों के बाद हुई अपनी पहली बैठक के बाद आयोग ने एक बयान में कहा कि निर्वाचन आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी द्वारा कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी से संबंधित थे, न कि नीतिगत या सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रभाग से जुड़े मामलों से। निर्वाचन आयोग की ये टिप्पणियां अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन एक्सप्रेस' की उस खबर की पृष्ठभूमि में आया, जिसमें कहा गया था कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े फैसलों पर कई मौकों पर आपत्ति जताई थी।

हालांकि, निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आंतरिक विचार-विमर्श के दौरान मतभेद सामने आना सामान्य है और उसके अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्वाचन आयोग के भीतर सामने आए कथित मतभेदों और आयोग की ओर से सार्वजनिक रूप से दिखाई गई एकजुटता के बीच अंतर को अपने पक्ष में इस्तेमाल करने की कोशिश की।

सार समाचार

पुणे पुलिस ने दी 'छात्र सत्याग्रह' की अनुमति

पुणे,एजेंसी। महाराष्ट्र में पुणे पुलिस ने दो अक्टूबर (गांधी जयंती) को प्रस्तावित महत्वपूर्ण 'छात्र सत्याग्रह' को औपचारिक रूप से अनुमति दे दी है। पहले यह प्रदर्शन किसी और तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन गणेशोत्सव के समापन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार के साथ उच्चस्तरीय चर्चा के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह शांतिपूर्ण आंदोलन पुणे में पत्रकार भवन के पास एस. एम. जोशी पुल के निकट आयोजित किया जाएगा।

अभ्यर्थी परीक्षा व्यवस्था में तत्काल पारदर्शिता लाने, मूल्यांकन में सामने आई विसंगतियों पर कार्रवाई करने और भ्रष्टाचार तथा प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) के अध्यक्ष को हटाने की मांग कर रहे हैं।

हरदोई में बारिश बनी आफत, 8 मौतें

हरदोई,एजेंसी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में 25 सितंबर से लगातार हो रही भारी बारिश अब जानलेवा साबित हो रही है। वर्षा जनित हादसों में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 6 मौतें दीवार या मकान गिरने से, जबकि 2 मौतें सर्पदंश से हुई हैं। इसके अलावा करीब 30 पशुओं की भी मौत हुई है और 330 मकान क्षतिग्रस्त या धराशायी हुए हैं।

बीते 48 घंटे से हरदोई में लगातार बारिश के चलते वर्षा जनित हादसो में सुरसा थाना क्षेत्र के खजुराहरा गांव के उम्मरपूरवा मजरे में कच्ची दीवार गिरने से 45 वर्षीय मकरंद पुत्र शिवलाल की मलबे में दबकर मौत हो गई। हादसे में एक गाय और एक बैल भी दबकर मर गए। प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

बघौली के बरबटापुर में शनिवार रात कच्ची दीवार गिरने से 50 वर्षीय आरती सिंह की मौत हो गई।

मुख्यमंत्री ने उज्जैन को दी 172 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

उज्जैन,एजेंसी।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को महाकालेश्वर मंदिर के समीप स्थित महाकाल महालोक में 172.87 करोड़ रुपये लागत के विभिन्न विकास एवं निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सम्पूर्ण राज्य में समान रूप से विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। अवंतिका प्राचीन काल से ही गौरवशाली और वैभवशाली नगरी रही है। उज्जैन के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए नागरिक स्वेच्छा से अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन को शीघ्र ही मेट्रो ट्रेन की सौगात भी मिलेगी। भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। ग्वालियर को नई मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा उसे टेलीकॉम सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। इंदौर-भोपाल-जबलपुर तक औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, जिससे पूरे प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। समारोह में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में उज्जैन का चौमुखी विकास हो रहा है तथा सिंहस्थ के दृष्टिगत नगर को सजाया-संवारा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कुल 15 कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया, जिसमें 12 कार्यों का भूमिपूजन और तीन कार्यों का लोकार्पण शामिल है।

मोहन यादव ने रविवार को महाकाल लोक स्थित अन्नक्षेत्र पार्किंग परिसर से पीएम ई-बस सेवा एवं उज्जैन दर्शन सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने शक्ति पथ, महाकाल लोक से बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर वेदपाठी बटुकों ने वेद मंत्रों का वाचन किया और डमरू वादन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्री महाकालेश्वर की नगरी में आज अद्भुत दिन है और शहर को लगातार विकास की नई सौगातें मिल रही हैं।

उन्होंने कहा कि 21 वर्ष पहले राज्य परिवहन निगम की बसें संचालित होती थीं, लेकिन बाद में सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद हो गई थी। अब इस कमी को पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन निगम की बसें एक राज्य से दूसरे राज्य तक तथा नगरीय स्तर पर शहर के भीतर भी संचालित होंगी। उज्जैन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 10 बसों की सौगात मिली है। कार्यक्रम में सांसद अनिल फिरोजिया, राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, एडीजी राकेश गुप्ता, डीआईजी नवनीत भसीन, संभागायुक्त आशीष सिंह, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

स्वस्थ शरीर के लिए योग-व्यायाम जरूरीः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को उज्जैन स्थित दशहरा मैदान पर आयोजित पंख मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने मंच पर विभिन्न योगासन कर प्रतिभागियों और योग साधकों का उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि परमात्मा की कृपा से हमारा शरीर स्वयं में एक लघु ब्रह्मांड है और इसे स्वस्थ एवं निरोग रखना हमारी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मां के गर्भ से आने के बाद हमारा शरीर पल-पल बदलता रहता है। शरीर की विशेषता है कि हम केवल आंखों से ही नहीं, बल्कि विभिन्न अंगों और स्पर्श के माध्यम से भी चीजों को अनुभव कर पहचान सकते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने में नियमित योग और व्यायाम का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि महाकाल की नगरी उज्जैन आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखती है।

कांग्रेस की भ्रम और मनगढ़ंत कहानियों की राजनीति पूरी तरह ध्वस्तः आदित्य साहू

रांची, एजेंसी।

झारखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि लूट, झूठ और फरेब कांग्रेस पार्टी के स्वभाव में शामिल है। ये लोग झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करते हैं तथा जनता को धोखा देते हैं।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री साहू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के द्वारा संवैधानिक संस्थाओं पर हमला किए जाने के खिलाफ हमला बोलते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी को बार बार नकार रही है, इससे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है।

चुनाव आयोग के आधिकारिक संयुक्त बयान से कांग्रेस और विपक्षी इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश हुआ और कांग्रेस की भ्रम और मनगढ़ंत कहानियों की राजनीति पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की बैठक और संयुक्त प्रेस नोट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कांग्रेस व विपक्ष सिर्फ और सिर्फ झूठ, सनसनी और भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया। तीनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए एसआईआर समेत सभी फैसले निष्पक्ष थे और चुनावी प्रक्रिया पर कांग्रेस के द्वारा सवाल उठाना उनकी हताशा का प्रतीक है।

साहू ने कहा कि कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा पत्र किसी नीतिगत विषय या एसआईआर से संबंधित नहीं था। 'द इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट कोरी कल्पना पर आधारित गढ़ी गई कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं थी। उन्होंने कहा कि एसआईआर के फॉर्म-6 के घोषणापत्र को माननीय सर्वोच्च न्यायालय पहले ही वैध ठहरा चुका है, विपक्ष की संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की साजिश फिर से एक बार नाकाम हुई। कांग्रेस अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और अन्य संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाकर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही है। चुनाव आयोग की स्पष्टता के बाद कांग्रेस के आरोपों की वास्तविकता सामने आ गई है, ऐसे में कांग्रेस को संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय तथ्यों का सम्मान करना चाहिए।

असहमति होना किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा हैः यादव

अलवर, एजेंसी।

केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रशासनिक और न्यायिक प्रक्रियाओं को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर कहा है कि असहमति होना किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इससे निर्णय प्रक्रिया रुकती नहीं है।

यादव ने यहां शनिवार रात पत्रकारों से कहा कि कुछ लोग प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता के बीच भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि अंतिम निर्णय संबंधित संस्था का होता है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग में दो आयुक्तों की टिप्पणियों के संदर्भ में कहा कि किसी भी सरकारी फाइल पर अलग-अलग अधिकारियों की राय अलग हो सकती है। दो अधिकारियों के बीच असहमति होने पर उनकी टिप्पणी दर्ज की जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी प्रक्रिया रुक गई है। यादव ने न्यायपालिका का उदाहरण देते हुए कहा कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ में भी कई बार न्यायाधीशों की राय अलग-अलग होती है और फैसला बहुमत के आधार पर होता है। इसके बावजूद अंतिम निर्णय पूरी संस्था का माना जाता है। उन्होंने केरल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) दर्ज होने के बावजूद चुनाव हुए। इसके बावजूद विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, लेकिन प्रक्रियाओं को लेकर भ्रम पैदा करना उचित नहीं है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वास्तविक स्थिति जनता के सामने है।

यादव ने चुनावी दावों को लेकर भी विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अलवर में कुछ लोग चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी बातें करते हुए 60 सीटें जीतने तक के दावे करते हैं, लेकिन उनके साथ बैठे लोग भी ऐसे दावे सुनकर हैरान रह जाते हैं।

उन्होंने कहा कि चुनावी राजनीति में दावे करना अलग बात है, लेकिन प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता के बीच भ्रम नहीं फैलाया जाना चाहिए।

खाद के लिए किसान बेहाल, सम्मान निधि बनी झुनझुना : संदीप मिश्रा

गोरमी, साहस समाचार।

भाजपा सरकार में किसान खाद के लिए कतारों में खड़ा होकर परेशान हो रहा है, जबकि दलाल और माफिया कथित तौर पर इसका फायदा उठा रहे हैं। किसान को न खाद मिल रही है और न ही फसलों का उचित मूल्य। यह आरोप सेवादल जिलाध्यक्ष संदीप मिश्रा ने रविवार को गोरमी नगर परिषद परिसर में आयोजित सेवादल के मासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान लगाया।

मिश्रा ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी अब केवल 'झुनझुना' बनकर रह गई है। उनका आरोप था कि सरकार की नीतियों से किसान परेशान है और उसे अपनी उपज का उचित दाम पाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है।

कार्यक्रम की शुरुआत नगर परिषद गोरमी परिसर में मुख्य अतिथि पूर्व जनपद अध्यक्ष रामहर्ष सिंह कुशवाह और वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगत सिंह द्वारा राष्ट्रध्वज फहराने के साथ हुई। इसके बाद वंदे मातरम् का गायन किया गया। पूर्व जनपद अध्यक्ष रामहर्ष सिंह कुशवाह ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों को फसल का उचित दाम मिलने के बजाय चुनावी वादों का सामना करना पड़ रहा है।

बस्तर में बाढ़ का कहर, 805 लोगों को बचाया

जगदलपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। डोंगाघाट सहित बाढ़ से घिरे क्षेत्रों में फंसे लोगों को निकालने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। रविवार सुबह तक जिले में 805 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 42 राहत शिविरों में 4,798 प्रभावितों ने शरण ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोंगाघाट क्षेत्र में बाढ़ के बीच कई लोगों के फंसे होने के बाद हवाई रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया।

सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। शुरुआत में 10 लोगों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाले जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद भी अभियान लगातार जारी रहा। बाढ़ के कारण शहर से लगे कुड़कानार क्षेत्र में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है।

कुशभवनपुर संदेश महाविशेषांक और सुल्तानपुर दर्पण-अतीत और वर्तमान का विमोचन

सुल्तानपुर, साहस समाचार।

वरिष्ठ पत्रकार सत्यदेव तिवारी की पत्रकारिता जीवन के 50 वर्ष पूर्ण होने पर अभिनंदन समारोह में संधीस प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उनकी दो पुस्तकों ('कुशभवनपुर संदेश' महाविशेषांक तथा 'सुल्तानपुर दर्पण-अतीत और वर्तमान') का पं. रामनरेश त्रिपाठी सभागार यूपी के सुल्तानपुर जिले में विमोचन हुआ।

कार्यक्रम में भाजपा के पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं लेखक डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि सत्यदेव तिवारी सहृदय व्यक्ति हैं, यही वजह है कि वह सबके मित्र हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद परिस्थितियां बदली हैं। शिक्षा का स्तर और जनसंख्या बढ़ने के बावजूद पत्र-पत्रिकाओं का प्रसार अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा है। ऐसी स्थिति में डिजिटल दौर में किसी पत्रिका का नियमित प्रकाशन अपने आप में चुनौती है।

डॉ. एमपी सिंह ने कहा कि आज के डिजिटल युग में जहां पत्र पत्रिकाएं धीरे-धीरे बंद हो रही हैं या कम होती जा रही हैं, ऐसे में सत्यदेव तिवारी ने नियमित रूप से कुशभनपुर संदेश प्रकाशित कर बहुत साहस का कार्य किया है।

वरिष्ठ पत्रकार त्रियुगी नारायण तिवारी ने कहा कि जब किताबों का दौर अस्ताचल की ओर जाता दिखाई दे रहा है, ऐसे समय में सत्यदेव तिवारी ने प्रकाशन और पत्रकारिता का रास्ता चुना है। यह प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है।

कार्यक्रम में डॉ. ओंकार नाथ द्विवेदी, डॉ. एके सिंह, डॉ. डीएस मिश्रा, डॉ. जेपी सिंह, साहित्यकार कमलनयन पांडे, सुशील पांडे, सोमेश शेखर, प्रबंधक शशि प्रकाश सिंह तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद श्रीवास्तव समेत अन्य वक्ताओं ने सत्यदेव तिवारी की पत्रकारिता यात्रा और उनके योगदान पर प्रकाश डाला। अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने कहा कि सुल्तानपुर के इतिहास से जुड़ी कृतियों के ऐतिहासिक विमोचन समारोह में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है।

विकसित उत्तराखंड विजन 2047 के लिए कार्ययोजना बनाने के निर्देश

हरिद्वार एजेंसी। उत्तराखंड में हरिद्वार के विकास भवन सभागार में रविवार को मुख्य विकास अधिकारी ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड विजन 2047 की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अगस्त 2026 की मासिक प्रगति रिपोर्ट में बी, सी और डी श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। सीडीओ ने संबंधित विभागों को आगामी माह में प्रगति में सुधार लाने के निर्देश दिए। बैठक में जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, एनआरएलएम, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) और जल जीवन मिशन की विशेष रूप से समीक्षा की गई। सीडीओ ने इन योजनाओं से जुड़े विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करते हुए अपनी प्रगति और श्रेणी में सुधार करने के निर्देश दिए।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठित होकर योजनाओं का लाभ गांव की अंतिम पंक्ति तक पहुंचाएं : संध्या राय

शशिकांत गोयल

भिण्ड, साहस समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्ष के सेवा एवं सुशासन के संकल्प के तहत जिला पंचायत सभागार में 'आंगन मिलन उत्सव' कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लोकसभा सांसद संध्या राय और भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह नरवरिया ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद संध्या राय ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को गांव की अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगिनियों से संवाद करने तथा उनके सम्मान का अवसर मिला।

सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, बच्चों और जरूरतमंद परिवारों तक सहायता पहुंचाई जा रही है। आंगनबाड़ी केंद्र केवल सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम नहीं, बल्कि ग्रामीण परिवारों से सीधे जुड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठित होकर शासन की योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पहुंचाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि गांव-गांव माताओं, बहनों और बच्चों के बीच काम करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का सेवाभाव समाज की जमीनी शक्ति का उदाहरण है। उनके समर्पण और निरंतर सेवा के सम्मान का उद्देश्य उनके योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है।

कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा सहयोगिनियों तथा लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना सहित विभिन्न योजनाओं के पात्र हितग्राहियों ने सांसद से संवाद किया। हितग्राहियों ने योजनाओं से मिले लाभ के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

कार्यक्रम के दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न पोषण आहार एवं खाद्य सामग्री का सांसद संध्या राय ने निरीक्षण किया और तैयार व्यंजनों का स्वाद भी लिया।

इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य कृष्णकांता तोमर, जिला उपाध्यक्ष पिंकी शर्मा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बबली, डॉ. योगेंद्र सिंह तोमर, पूर्व जिलाध्यक्ष आभा जैन, बाल एवं महिला कल्याण समिति सदस्य सीमा शर्मा, जनपद अध्यक्ष सरोज बघेल, पूर्व जिला महामंत्री पूर्णिमा भदौरिया, अनीता चोपड़ा सहित जिला पंचायत सीईओ और महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

राष्ट्रीय पार्टी में पद दिलाने के नाम पर 82.63 लाख की ठगी

बिलासपुर,एजेंसी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक युवक ने राष्ट्रीय पार्टी में पद दिलाने का झांसा देकर 82 लाख 63 हजार 194 रुपए की ठगी किए जाने का आरोप लगाया है। पीड़ित की शिकायत पर सरकंडा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत के अनुसार सरकंडा क्षेत्र निवासी चेतन आनंद दुबे की पिछले वर्ष फेसबुक के माध्यम से खोंगापानी, मनेंद्रगढ़ निवासी निखत परवीन साबरी से पहचान हुई थी। चेतन का आरोप है कि बातचीत के दौरान निखत ने खुद को एक राष्ट्रीय पार्टी का कार्यकर्ता बताया और पार्टी के बड़े नेताओं से संपर्क होने की बात कही। इसी दौरान गतौरी में चेतन की जमीन से संबंधित विवाद में निखत ने पटवारी और राजस्व निरीक्षक से जुड़ा काम कराने में मदद की, जिससे उसका उस पर भरोसा बढ़ गया।

शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद निखत ने चेतन को पार्टी में पद दिलाने का प्रस्ताव दिया।

एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों को संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बताते हुए विपक्ष को आत्मावलोकन की नसीहत दी

कांग्रेस-सपा जीतें तो पुरुषार्थ, हारें तो चुनाव आयोग दोषी: योगी

लखनऊ,एजेंसी।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एसआईआर को लेकर विपक्ष की आपत्तियों के बीच रविवार को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस-सपा समेत विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं तो इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन हारने पर चुनाव आयोग और ईवीएम को दोष देने लगते हैं।

उन्होंने एसआईआर को लेकर उठाए जा रहे सवालों को संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश बताते हुए विपक्ष को आत्मावलोकन की नसीहत दी। मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस, सपा, राजद और अन्य विपक्षी दलों को निशाने पर रखते हुए कहा कि एसआईआर को लेकर भ्रम पैदा कर हाय-तौबा मचाई जा रही है।

चुनाव आयोग की ओर से पूरी स्थिति स्पष्ट किए जाने के बाद भी सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने की यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक मूल्यों और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कमजोर करती है। एसआईआर को पहली बार की जा रही कवायद बताने पर मुख्यमंत्री योगी ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में 1952, 1957, 1961, 1965-66 और 2003 में भी एसआईआर की कार्रवाई हो चुकी है।

इनमें ज्यादातर समय केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसके बावजूद इस बार कांग्रेस, सपा, राजद और अन्य विपक्षी दलों की ओर से एसआईआर को लेकर भ्रम फैलाना दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली कांग्रेस आज चुनाव आयोग को ही कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस, सपा और राजद चुनाव जीत जाएं तो इसे अपना पुरुषार्थ बताते हैं, लेकिन अपनी नीतियों, भ्रष्टाचार, आर्थिक कदाचार और अराजकता के कारण जनता उन्हें खारिज कर दे तो चुनाव आयोग और ईवीएम को जिम्मेदार ठहराते हैं। उन्होंने विपक्षी दलों को इस पर चिंतन और आत्मावलोकन करने की नसीहत दी। मुख्यमंत्री योगी ने चुनाव आयोग पर उठाए जा रहे सवालों को विपक्ष की पुरानी कार्यप्रणाली से जोड़ा। राहुल गांधी के कैंब्रिज में दिए बयान का उल्लेख करते हुए उन्होंने न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठाने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि 2019 में राफेल के मुद्दे पर कैग के ऑब्जर्वेशन पर भी सवाल उठाए गए। जिस ईवीएम से कांग्रेस की केंद्र और राज्यों में सरकारें बनीं, उसी को ब्लैक बॉक्स बताकर देश की चुनाव प्रणाली को कठघरे में खड़ा किया गया। उन्होने आरोप लगाया कि संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल खड़े करने से देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर होती है और दुनिया में भारत की छवि पर भी असर पड़ता है।

कांग्रेस पर हमला तेज करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने 25 जून 1975 के आपातकाल की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संवैधानिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर कितना विश्वास रहा है, इसे देश जानता है। उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकारों पर विपक्षी दलों की चुनी हुई सरकारों को अनैतिक और अवैध तरीके से गिराने का भी आरोप लगाया।

बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर भारतीय जवानों के शौर्य और पराक्रम को कटघरे में खड़ा करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि जवानों के पराक्रम पर सवाल उठाना कहां की देशभक्ति है।

मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बने पवन

भिंड, साहस समाचार।

लहार क्षेत्र के ग्राम रावतपुरा खुर्द, दबोह निवासी पवन कुमार त्रिपाठी ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प से परिवार के साथ-साथ गांव और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। वर्ष 2026 में उन्होंने मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयन प्राप्त किया। उनकी सफलता से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है।

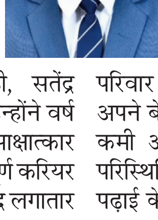

पवन कुमार त्रिपाठी, सतेंद्र कुमार त्रिपाठी के पुत्र हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में एमपीपीएससी के साक्षात्कार के माध्यम से अपने संघर्षपूर्ण करियर की शुरुआत की। इसके बाद लगातार प्रयास करते हुए उनका चयन पुरातत्व विभाग, चेन्नई, जेएएच अस्पताल, ग्वालियर में सोशल वर्कर तथा बाद में वेलफेयर ऑफिसर, दिल्ली सहित विभिन्न पदों पर हुआ। चार अलग-अलग नौकरियों में चयन के बावजूद पवन ने अपने मूल लक्ष्य को नहीं छोड़ा। नौकरी के साथ उन्होंने अध्ययन और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रखी। वर्षों की मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास का परिणाम रहा कि वर्ष 2026 में उन्होंने मध्य प्रदेश में 7वीं रैंक हासिल कर असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर चयन प्राप्त किया।

पवन की सफलता में उनके पिता सतेंद्र कुमार त्रिपाठी के संघर्ष और समर्पण की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसान परिवार से होने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे की शिक्षा में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी। कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने पवन को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया और हर कदम पर उनका साथ दिया। पवन कुमार त्रिपाठी की उपलब्धि यह संदेश देती है कि परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हों, स्पष्ट लक्ष्य, निरंतर मेहनत और धैर्य के साथ सफलता हासिल की जा सकती है।

अनाहत सिंह और अभय ने स्क्वाश में जीता रजत पदक

फाइनल में अपने-अपने मलेशियाई प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दोनो खिलाडियों को मिली हार।

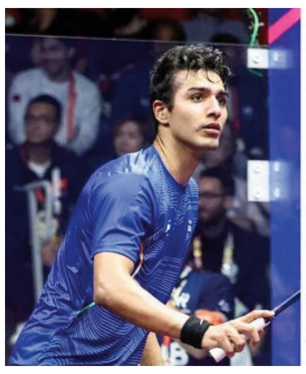

नागोया,एजेंसी। भारत का स्क्वाश में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक का इंतजार जारी रहा जब अनाहत सिंह और अभय सिंह को रविवार को यहां एशियाई खेलों के फाइनल में अपने-अपने मलेशियाई प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अभय पुरुष एकल फाइनल में ईन यो एनजी के खिलाफ कड़ी चुनौती पेश करने में नाकाम रहे और सीधे गेम में 44 मिनट में 9-11, 5-11, 5-11 से हार गए। अट्ठारह वर्षीय अनाहत को भी महिला एकल फाइनल में मलेशिया की शिवासांगरी सुब्रमण्यम ने आसानी से हराया। दुनिया की 17वें नंबर की भारतीय खिलाड़ी को पांचवीं रैंकिंग वाली शिवासांगरी के खिलाफ 4-11, 4-11, 7-11 से शिकस्त मिली।

इस नतीजे का मतलब है कि अनाहत और अभय दोनों 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने से चूक गए जहां स्क्वाश पहली बार ओलंपिक खेलों का हिस्सा बनेगा। अब भारतीय खिलाड़ियों को क्वालीफाई करने के लिए दूसरे रास्ते तलाशने होंगे। स्क्वाश में किसी भी भारतीय ने अब तक व्यक्तिगत वर्ग में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक नहीं जीता है। सौरव घोषाल भी दो बार इसके करीब पहुंचे थे लेकिन उन्हें भी 2014 के इंचियोन और 2023 के हांगझोउ एशियाई खेलों में रजत पदक से संतोष करना पड़ा था।

यो और शिवासांगरी दोनों ने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करने वाले शुरुआती दो खिलाड़ी बनकर इतिहास रचा। दोनों ने अपने एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक का भी सफलतापूर्वक बचाव किया। विश्व जूनियर खिताब जीतने वाली पहली भारतीय अनाहत शनिवार को जापान की दुनिया की छठे नंबर की खिलाड़ी सातोमी वातानाबे के खिलाफ सेमीफाइनल में की गई वापसी को दोहरा नहीं सकीं। अनाहत-सातोमी सेमीफाइनल को करीब से देखने वाली शिवासांगरी स्पष्ट रणनीति के साथ उतरीं और उसे पूरी तरह से अमल में भी लाईं।

मलेशियाई खिलाड़ी ने अनाहत को लगातार विनर्स लगाने का मौका नहीं दिया और लगातार आक्रमण के जरिए उन पर दबाव बनाए रखा। हालांकि अनाहत के लिए यह अभियान यादगार रहा। उन्होंने एशियाई खेलों के इतिहास में महिला एकल फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले 26वीं रैंकिंग वाले अभय भी दुनिया के 18वें नंबर के यो को कड़ी चुनौती नहीं दे सके। यो ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए अपने खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। यह अभय की मलेशियाई खिलाड़ी के खिलाफ आठवीं हार है।

तिरुवनंतपुरम में कोहली का विस्फोटक शतक, भारत ने वेस्टइंडीज को 8 विकेट से रौंदा

तिरुवनंतपुरम। भारत ने विराट कोहली और कप्तान शुभमन गिल की शतकीय पारियों के दम पर वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच में 8 विकेट से जीत हासिल की। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित इस मुकाबले को अपने नाम करते हुए मेजबान देश ने तीन मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने निर्धारित ओवरों में 7 विकेट खोकर 295 रन बनाए।

जॉन कैंपबेल ने जस्टिन ग्रीव्स के साथ पहले विकेट के लिए 19.2 ओवरों में 135 रन की साझेदारी की। कैंपबेल 60 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 62 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ग्रीव्स ने कीसी कार्टी के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन जुटाकर टीम को 176 के स्कोर तक पहुंचा दिया।कार्टी वेस्टइंडीज के खाते में 13 रन जोड़कर आउट हुए, जिसके बाद टीम लड़खड़ा गई। आलम ये रहा कि 198 के स्कोर तक 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। इस बीच ग्रीव्स 108 गेंदों में 12 चौकों के साथ 101 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे।

यहां से आमिर जंगू ने 43 गेंदों में नाबाद 58 रन, जबकि रोस्टन चेज ने 24 रन की पारी खेलते हुए मेहमान टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। टीम इंडिया के लिए कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट निकाले। नितीश रेड्डी को 1 विकेट हाथ लगा।इसके जवाब में भारत ने 41.4 ओवरों में मुकाबला अपने नाम कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 12 ओवरों में 74 रन की साझेदारी की। रोहित 35 गेंदों में 3 छक्कों और 2 चौकों के साथ 32 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद विराट कोहली ने मोर्चा संभाला।कोहली ने कप्तान के साथ दूसरे विकेट के लिए 132 गेंदों में 151 रन की साझेदारी करते हुए भारत को 225 के स्कोर तक पहुंचा दिया।

एंसी सोजन को लंबी कूद में रजत, हरिता ने 200 मीटर में कांस्य जीता

नागोया,एजेंसी। भारत की एंसी सोजन ने रविवार को यहां एशियाई खेलों की महिला लंबी कूद स्पर्धा में अधिकांश समय बढ़त बनाए रखी लेकिन अंत में उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। एंसी 6.53 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास से दूसरे स्थान पर रहीं। चीन की हुआंग यिंगयिंग ने आखिरी प्रयास में 6.55 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की हरिता भद्रा ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ के फाइनल में 23.20 सेकेंड का समय निकालकर कांस्य पदक जीता। भद्रा जापान की इडो अबिगेइरुफुका से ठीक आगे तीसरे स्थान पर रहीं। इडो ने 23.21 सेकेंड का समय लिया।

हालांकि एंसी की हमवतन शैली सिंह को महिला लंबी कूद फाइनल में निराशा हाथ लगी। चीन की मेंगयी तान ने 6.46 मीटर की कूद लगाकर भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ दिया जिससे शैली कांस्य पदक से चूक गईं। एंसी ने अपने पांचवें प्रयास में 6.53 मीटर की कूद लगाई थी लेकिन यिंगयिंग ने अंतिम प्रयास में 6.55 मीटर की कूद के साथ भारतीय खिलाड़ी को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

शैली का दिन का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 6.42 मीटर रहा। महिला 200 मीटर फाइनल में सिंगापुर की शांति परेरा ने सत्र के सर्वश्रेष्ठ 22.78 सेकेंड के समय से स्वर्ण पदक जीता।

भारत के तीन मुक्केबाजों ने एशियाई खेलों में पदक पक्के

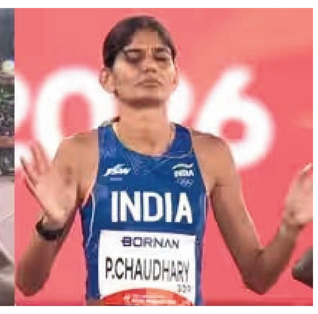

निशियो,एजेंसी। भारतीय मुक्केबाज परवीन हुड्डा, अंकुश पंघाल और नरेंदर बेरवाल ने रविवार को यहां क्वार्टरफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर देश के लिए तीन पदक पक्के किए जबकि सचिन सिवाच का अभियान अंतिम आठ चरण में समाप्त हो गया। पिछले महीने ग्लास्गो में राष्ट्रमंडल खेलों का स्वर्ण जीतने वाले अंकुश ने पुरुषों के 80 किग्रा क्वार्टरफाइनल में ताजिकिस्तान के नेकरूज सालिमोव के खिलाफ 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से जीत दर्ज कर शुरुआत की।

नरेंदर (90 किग्रा से अधिक) ने पिछले चरण के अपने कांस्य पदक में एक और पदक जोड़ लिया। थाईलैंड के अद्थापोंग साएंगटेप के खिलाफ क्वार्टरफाइनल मुकाबले में दो मिनट से भी कम समय में रेफरी ने मुकाबला रोक (आरएससी) दिया। भारत के सुपर हैवीवेट मुक्केबाज ने अपने थाई प्रतिद्वंद्वी पर जोरदार मुक्कों की बौछार कर दी जिससे रेफरी को मुकाबला रोकने से पहले साएंगटेप को तीन स्टैंडिंग काउंट देने पड़े।

परवीन ने उज्बेकिस्तान की विश्व चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता नवबखोर खामिदोवा को इसी अंतर से हराकर महिलाओं के 65 किग्रा सेमीफाइनल में जगह बनाई। पिछले चरण में परवीन का कांस्य पदक उनसे छीन लिया गया था क्योंकि डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) ने ठिकाने की जानकारी देने में विफल रहने के कारण उन पर प्रतिबंध लगा दिया था। हरियाणा की मुक्केबाज का यह पहला मुकाबला था क्योंकि पिछले दौर में उन्हें वॉकओवर मिला था। लेकिन परवीन ने खामिदोवा पर मुक्कों की झड़ी लगाते हुए शानदार प्रदर्शन किया।

हालांकि राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन सचिन का सफर खत्म हो गया। वह पुरुषों के 60 किग्रा क्वार्टरफाइनल में जापान के स्थानीय पसंदीदा शुनसुके कितामोटो से 0-5 से हार गए। अंकुश ने सलीमोव को पूरी तरह पछाड़ते हुए दबदबे वाला प्रदर्शन किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की। एशियाई खेलों में पदार्पण कर रहे अंकुश इस तरह अंतिम चार में पहुंच गए और कम से कम कांस्य पदक पक्का कर लिया।

एशियाई खेलों में पदार्पण कर रहे हरियाणा के इस मुक्केबाज ने मजबूत शुरूआत की और सीधे बायें और दायें हुक जैसे सटीक पंच लगाकर सालिमोव को दबाव में रखा। सालिमोव ने पलटवार की कोशिश की लेकिन उनके हमलों में दम नहीं था। पहले दौर में सभी पांच जज का फैसला अंकुश के पक्ष में रहा। दूसरे दौर में भी उन्होंने यही लय बनाये रखी और फिर पांचों जज के स्कोरकार्ड पर यह दौर भी अपने नाम किया। आखिरी दौर में भी सालिमोव पर दबाव बना रहा।

भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को 7-0 से हराया

काकामिगाहारा,एजेंसी। सुनेलिता टोप्पो के दो गोल की मदद से भारतीय महिला हॉकी टीम ने रविवार को यहां एशियाई खेलों के अपने अंतिम पूल बी मैच में सिंगापुर को 7-0 से रौंद दिया जिससे अब सेमीफाइनल में उसका सामना कोरिया से होगा। भारत ने पांच मैच में पांच जीत के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। अब सेमीफाइनल 30 सितंबर को होगा। भारत के लिए कप्तान सलीमा टेटे (17वें मिनट), सुनेलिता (22वें, 24वें), लालरेमसियामी (26वें), रुतुजा दादासो पिसाल (29वें), निक्की प्रधान (35वें) और दीपिका (55वें) ने गोल किए।

गत चैंपियन और मौजूदा ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान जापान से भिड़ेगा।

सिंगापुर ने पहले क्वार्टर में भारत को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत ने दबदबा बनाए रखा। सिंगापुर ने भारत के शुरुआती आठ पेनल्टी कॉर्नर नाकाम किए। दूसरे क्वार्टर में सलीमा ने मैदानी गोल से भारत का खाता खोला। इसके बाद सुनेलिता ने दो गोल किए जबकि ललरेमसियामी और रुतुजा ने भी गोल कर भारत को 5-0 से आगे कर दिया। तीसरे क्वार्टर में निक्की ने भारत की बढ़त 6-0 कर दी। भारत को लगातार पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम उन्हें गोल में बदलने में नाकाम रही।

बिजनेस

वैश्विक कारकों से तय होगी शेयर बाजार की दिशा

मुंबई,एजेंसी। बीते सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में घरेलू शेयर बाजारों की दिशा कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तथा अन्य वैश्विक कारकों से तय होगी। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इन दिनों कच्चे तेल में काफी उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।

चीनी में 176 रुपये की साप्ताहिक गिरावट, खाद्य तेलों के भाव चढ़े

नई दिल्ली,एजेंसी। घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चीनी 176 रुपये सस्ती हुई। चावल, गेहूं और खाद्य तेलों के दाम चढ़ गए जबकि दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा। बीते सप्ताह मीठे के बाजार में चीनी का औसत भाव 176 रुपये गिरकर सप्ताहांत पर 5,167 रुपये प्रति क्विंटल रह गया। गुड़ का भाव 46 रुपये प्रति क्विंटल उतर गया।

तेजी से आगे बढ़ रहा भारत का यूपीआई, नए शुल्क से निवेश को मिलेगा प्रोत्साहन

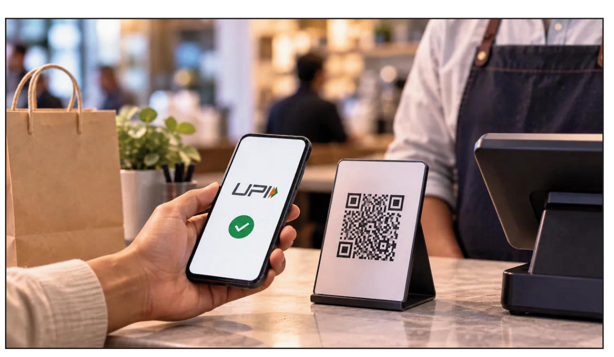

नई दिल्ली,एजेंसी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) द्वारा संचालित यूपीआई भुगतान प्रणाली लेनदेन की मात्रा के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट-पेमेंट सिस्टम है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआई ने भारत में डिजिटल क्रांति को गति दी है। इसने आबादी के बड़े हिस्से को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने में मदद की है और डिजिटल अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक भुगतान रोजमर्रा के कारोबार का तेजी से महत्वपूर्ण हिस्सा बनते जा रहे हैं।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में वार्षिक यूपीआई लेनदेन की संख्या बढ़कर 241.62 अरब हो गई, जो 2016-17 में 17.8 मिलियन थी। इसी अवधि में लेनदेन का मूल्य 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.14 लाख करोड़ रुपए हो गया। अब सरकार यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) शुरू किए जाने के एक दशक बाद बड़े व्यापारियों से इसके इस्तेमाल के लिए शुल्क लेने पर विचार कर रही है, जिससे लंबे समय में यह प्रणाली टिकाऊ बनी रहे और इसे जारी रखने में आ रही लागत को रिकवर किया जा सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आय का एक निश्चित और अनुमानित स्रोत बैंकों तथा भुगतान कंपनियों को साइबर सुरक्षा, धोखाधड़ी का पता लगाने और विवादों के समाधान में निवेश करने के लिए अधिक प्रोत्साहित करेगा। साथ ही, इससे यूपीआई के अगले चरण को विकसित करने में भी मदद मिलेगी, जिसमें संभवतः क्रेडिट लाइन उपलब्ध कराना और सीमा-पार भुगतान का विस्तार शामिल होगा।

रिपोर्ट में एक विशेषज्ञ के हवाले से कहा गया, एशिया और ग्लोबल साउथ की कई भुगतान प्रणालियों ने यूपीआई का अध्ययन इसलिए किया है क्योंकि इसने साबित किया कि वीजा, मास्टरकार्ड या किसी विदेशी बोर्डरूम को भुगतान स्विच का नियंत्रण दिए बिना भी बड़े पैमाने पर प्रणाली का विस्तार किया जा सकता है। पोर्ट में फिनटेक कंपनी बिज2क्रेडिट के सह-संस्थापक और सीईओ रोहित अरोड़ा के हवाले से यह भी कहा गया है कि इतने वर्षों तक मुफ्त इस्तेमाल के बाद व्यापारियों से कुछ लागत वसूलना अपरिहार्य था।

यूपीआई नेटवर्क अब सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया, ग्रीस और उज्बेकिस्तान सहित 11 देशों में काम कर रहा है। भारतीय पर्यटक, कारोबारी यात्री और छात्र अपने भारतीय बैंक खातों से सीधे व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) भुगतान कर सकते हैं। इससे विदेशी मुद्रा पर लगने वाले मार्कअप की परेशानी खत्म होती है और अंतरराष्ट्रीय कार्ड या नकदी पर निर्भरता कम होती है। यह पहल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाती है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों में उनकी भुगतान प्रणालियों के लिए शुल्क की अलग-अलग दरें हैं, जो व्यापारी की श्रेणी और लेनदेन के आकार पर निर्भर करती हैं। इसी तरह, मलेशिया में ड्यूइटनाउ के व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क बैंक या भुगतान सेवा प्रदाता पर निर्भर करता है और कुछ मामलों में शुल्क में छूट भी उपलब्ध है।

तमिलनाडु में चावल महंगा, धान की कमी से कई किस्मों के दाम बढ़े

चेन्नई,एजेंसी। तमिलनाडु में धान के उत्पादन में गिरावट और पड़ोसी राज्यों से आपूर्ति कम होने के कारण पिछले एक महीने में चावल की कई लोकप्रिय किस्मों की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक असर पोन्नी चावल की कीमतों पर पड़ा है, जो राज्य के अधिकांश घरों में मुख्य खाद्यान्न के रूप में इस्तेमाल होता है। बाजार में पोन्नी चावल की कीमत 65 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 78 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं, मन्नाचनल्लूर पोन्नी 60 रुपये से बढ़कर 68 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया है। प्रीमियम पोन्नी की कीमत 65 रुपये से बढ़कर 82 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई है।

इसी तरह आईआर-20 चावल की कीमत भी पिछले महीने के 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 60 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सामान्य कच्चे चावल (रॉ राइस) का दाम भी 45 रुपये से बढ़कर कई दुकानों में 68 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। व्यापारियों के अनुसार पिछले 50 दिनों में चावल की कीमतों में तीन बार बदलाव किया गया है। उनका कहना है कि यदि दूसरे राज्यों से आपूर्ति कम रही और कुरुवई धान की फसल कमजोर रही तो कीमतों पर दबाव बना रह सकता है।

कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कम बारिश और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलने से धान की खेती प्रभावित हुई है। वहीं आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में भी धान की पैदावार घटने से तमिलनाडु की राइस मिलों तक पहुंचने वाले धान की मात्रा कम हो गई है। राइस मिल मालिकों का कहना है कि दूसरे राज्यों से आने वाले धान की खरीद कीमत पिछले सीजन के 32 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर करीब 44 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। उनका मानना है कि अप्रैल की कमजोर फसल के कारण धान की आवक घटी है। फिलहाल थोक बाजार में फाइन पोन्नी चावल करीब 75 रुपये प्रति किलोग्राम बिक रहा है।

तमिलनाडु में पोन्नी चावल की मांग अधिक है, लेकिन राज्य में इसकी खेती अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में पड़ोसी राज्यों की फसल प्रभावित होने का सीधा असर इसकी कीमतों पर पड़ता है। हालांकि, मिल मालिकों को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में नई फसल की आवक बढ़ने से धान की आपूर्ति सुधरेगी और चावल की कीमतों में स्थिरता आ सकती है। दूसरी ओर खुदरा व्यापारी अभी भी कीमतों में और बढ़ोतरी की आशंका जता रहे हैं।

भारत के रिन्यूएबल एनर्जी हब खावड़ा को मिला अपना पिन कोड

अहमदाबाद,एजेंसी। भारत के रिन्यूएबल एनर्जी हब को एक अलग भौगोलिक पहचान देते हुए गुजरात के कच्छ स्थित खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को अपना अलग डाक सूचकांक नंबर (पिन कोड) 370246 मिल गया है। इसके साथ ही यहां इंडिया पोस्ट का अपना डिलीवरी कार्यालय भी शुरू किया गया है। खावड़ा पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट, पार्सल बुकिंग और डिलीवरी, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक की सुविधाएं और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाएं उपलब्ध होंगी। इनमें आधार-आधारित डिजिटल बैंकिंग भी शामिल है।

यह समर्पित डाक सुविधा ऐसे समय में शुरू की गई है, जब खावड़ा कच्छ के कम आबादी वाले इलाके से विकसित होकर एक बड़े रिन्यूएबल एनर्जी हब में बदल गया है। यहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है, आवासीय टाउनशिप विकसित हो रही हैं और सहायक बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। इससे पहले इलाके की डाक सेवाएं करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित पोस्ट ऑफिस और कुरान ब्रांच पोस्ट ऑफिस के जरिए संचालित होती थीं। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के विस्तार और यहां रहने तथा काम करने वाले लोगों की बढ़ती संख्या के साथ एक समर्पित डाक सुविधा की जरूरत महसूस की जा रही थी।

नया पिन कोड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को एक अलग डाक पता देता है। इससे यह सीधे इंडिया पोस्ट के डिलीवरी नेटवर्क से जुड़ गया है और साइट पर मौजूद कारोबारों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। पिन कोड की व्यापक भूमिका बैंकिंग, बीमा, लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स सेवाओं की उपलब्धता तय करने में भी होती है।

खावड़ा के लिए '370246' इस रिन्यूएबल एनर्जी हब को एक विशिष्ट भौगोलिक पहचान देता है। यह इसे आसपास के क्षेत्रों से अलग करता है और आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचे के विकास और रणनीतिक राष्ट्रीय महत्व के केंद्र के रूप में इसके बढ़ते महत्व को दर्शाता है। समर्पित पिन कोड इस बात का एक और उदाहरण है कि क्षेत्र में अदाणी समूह द्वारा रिन्यूएबल एनर्जी परियोजना का विकास शुरू किए जाने के बाद से खावड़ा किस तरह बदल गया है। रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) और अन्य डेवलपर्स द्वारा विकसित किया जा रहा है। एजीईएल का प्लांट करीब 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की डेडलाइन नजदीक

नई दिल्ली,एजेंसी। वित्त वर्ष 2025-26 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 तेजी से नजदीक आ रही है। हालांकि, देशभर के कर पेशेवर और विभिन्न उद्योग संगठनों द्वारा इस समयसीमा को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की ओर से कोई आधिकारिक विस्तार घोषित नहीं किया गया है। ऐसे में टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले करदाताओं को मौजूदा समयसीमा को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां पूरी करने की सलाह दी जा रही है। आयकर विभाग के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं को 30 सितंबर तक अपना ऑडिट पूरा कराकर ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त करनी होती है।

विभिन्न पेशेवर संगठनों का कहना है कि इस बार ऑडिट, मिलान, खुलासों और अन्य अनुपालन कार्यों में अधिक समय लग रहा है। इसी वजह से कई संगठनों ने समयसीमा बढ़ाने की मांग की है। मध्य प्रदेश टैक्स कंसल्टेंट्स एसोसिएशन (एमपीटीसीए) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 30 नवंबर 2026 करने की मांग की है। हालांकि, जब तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती, तब तक 30 सितंबर की समयसीमा ही लागू मानी जाएगी। ऐसे में टैक्सपेयर्स को ये 5 जरूरी काम तुरंत कर लेने चाहिए।

पहला, करदाताओं को अपने लेखा-जोखा, बिक्री और खरीद रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, बिल, चालान और अन्य आवश्यक दस्तावेज व्यवस्थित रखने चाहिए। अधूरी जानकारी या रिकॉर्ड में विसंगतियां ऑडिट प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। दूसरा, कारोबारियों को जीएसटी टर्नओवर, कर विवरण और अन्य वित्तीय आंकड़ों का पुस्तकों से मिलान करना चाहिए। साथ ही फॉर्म 26एएस, एआईएस (एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट) और टीआईएस (टैक्सपेयर इन्फॉर्मेशन समरी) में उपलब्ध सूचनाओं की भी जांच करनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार की त्रुटि या असंगति समय रहते दूर की जा सके।

तीसरा, ऋण, स्थायी परिसंपत्तियों (फिक्स्ड एसेट्स), संबंधित पक्षों, वैधानिक देनदारियों और बड़े खर्चों जैसे मामलों की विशेष जांच करनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले इन सभी लेनदेन की टैक्स ट्रीटमेंट को लेकर ऑडिटर से चर्चा करना जरूरी है। चौथा, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दर्ज आंकड़ों का एक-दूसरे से मेल खाना आवश्यक है। टर्नओवर, खर्च, कटौतियां, कर संबंधी खुलासे और आगे ले जाए गए घाटे जैसे आंकड़ों में अंतर होने पर बाद में परेशानी हो सकती है।

और पांचवां, केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड कर देना पर्याप्त नहीं है। रिपोर्ट अपलोड होने के बाद करदाता को अपने आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग-इन कर उसे स्वीकृत भी करना होता है। इसलिए इस प्रक्रिया के लिए पर्याप्त समय पहले से निकालना जरूरी है। कई करदाता टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और आयकर रिटर्न की अंतिम तिथियों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।

'मेरी हिम्मत, मेरा सुकून'

नेहा धूपिया ने अपनी मां के लिए जन्मदिन पर लिखा खास नोट

मुंबई। एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी नेहा धूपिया ने अपनी मां मनपिंदर धूपिया को जन्मदिन की दिल से बधाई दी। उन्होंने अपनी मां को अपना सहारा, सुकून और खास इंसान बताया। नेहा ने अपनी मां की अच्छी सेहत और खुशी की भी कामना की।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक्ट्रेस ने अपनी मां की कई तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे मां... मेरा सहारा, मेरा सुकून, मेरा खास इंसान... हम हर दिन आपको सेलिब्रेट करते हैं... आपकी अच्छी सेहत और खुशी से बढ़कर मैं और कुछ नहीं चाहती... बाकी बातें हमारी पसंदीदा चाय-कॉफी के समय पर होंगी।'

तस्वीरों में नेहा अपनी मां के साथ पोज देती दिख रही हैं। एक तस्वीर में मां-बेटी की जोड़ी अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में आशीर्वाद लेती दिख रही है, जबकि एक और कैंडिड पल में वे खुलकर हंसती हुई नजर आ रही हैं। नेहा ने बर्थडे केक की झलक दिखाने वाला एक वीडियो भी शेयर किया।

नेहा धूपिया का अपनी मां मनपिंदर 'बबली' धूपिया के साथ बहुत करीबी और खास रिश्ता है। वह उन्हें अपनी ताकत और सपोर्ट का सबसे बड़ा जरिया मानती हैं। एक्ट्रेस ने अक्सर बताया है कि उनकी मां उनकी राजदार रही हैं और वे पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में सलाह के लिए उन्हीं के पास जाती हैं।

नेहा ने अक्सर एक पेरेंट के तौर पर अपने सफर के लिए अपनी मां को प्रेरणा माना है। पति अंगद बेदी के साथ अपने बच्चों, मेहर और गुरिक के आने के बाद, उन्होंने कहा है कि वह अपनी बेटी के लिए वैसी ही प्यार करने वाली और सपोर्टिव मां बनना चाहती हैं, जैसी उनकी मां उनके लिए रही हैं।

एक इंटरव्यू में, 'जूली' एक्ट्रेस ने बताया था कि कैसे उनकी मां उनके करियर और पारिवारिक जीवन के मुश्किल दौर में उनके साथ खड़ी रहीं।

पूनम ढिल्लों ने लता मंगेशकर को किया याद

बोलीं- उनके बिना अधूरा है हिंदी फिल्मों का संगीत

मुंबई। मुंबई स्थित टैगोर थिएटर में आयोजित 'सुरीला सफर-30: एन इवनिंग ऑफ बॉलीवुड मेलोडीज' में बॉलीवुड की सदाबहार धुनों के साथ महान गायिका लता मंगेशकर की संगीत विरासत को याद किया गया। इस कार्यक्रम में एक्ट्रेस पूनम ढिल्लों शामिल हुईं और लता जी के साथ जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा कीं। उन्होंने बताया कि उनके लंबे फिल्मी करियर में लता मंगेशकर की आवाज का खास हिस्सा रहा है। उन्होंने उनके लिए कई गाने गाए थे। लता जी के बिना हिंदी फिल्मों का संगीत अधूरा होता है।

आईएएनएस से खास बातचीत में पूनम ढिल्लों ने लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा, "लता मंगेशकर हम सभी के लिए बहुत प्यारी हैं। उनके बिना हिंदी फिल्मों का संगीत अधूरा होता है। यह देख अच्छा लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें याद किया जा रहा है। वह भी मेरे प्यारे टैगोर थिएटर में। यह मेरे लिए बेहद खुशी की बात है।"

पूनम ने कहा, "टैगोर थिएटर से मेरा रिश्ता काफी पुराना है। मैं बचपन से यहां आयोजित कॉन्सर्ट में आती रही हूं। इसलिए इसी जगह पर लता मंगेशकर को याद करने वाले कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए खास है। लता जी के साथ काम करना हमेशा यादगार रहेगा। उनके गाए सभी गाने बेहद खूबसूरत थे। अपने करियर में मैंने जितनी फिल्मों में काम किया, उनमें से केवल एक-दो फिल्मों को छोड़कर बाकी में लता मंगेशकर की आवाज है।"

बता दें कि 'सुरीला सफर-30' के जरिए बॉलीवुड की उन मेलोडी को याद किया जाता है, जो आज भी लोगों के बीच अपनी जगह बनाए हुए हैं। कार्यक्रम में लता मंगेशकर की संगीत यात्रा को याद किया गया। उनकी आवाज में रिकॉर्ड किए गए कई गाने आज भी अलग-अलग पीढ़ियों के बीच सुने जाते हैं और हिंदी फिल्म संगीत की पहचान से जुड़े हुए हैं।

गौरतलब है कि लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को 92 साल की उम्र में निधन हो गया था। कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जाता है कि इलाज के दौरान कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, जिसके बाद उनका निधन हो गया।

'जाने-अनजाने किसी को दुख पहुंचा हो तो माफ करें', अंकिता लोखंडे और विक्की जैन ने मांगी 'उत्तम क्षमा'

मुंबई। एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और उनके पति विक्की जैन ने 'उत्तम क्षमा' के मौके पर सभी से माफी मांगी। बता दें कि 'उत्तम क्षमा' दिगंबर जैन परंपरा में बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दौरान दिगंबर जैन समुदाय के लोग आध्यात्मिक चिंतन, पूजा-पाठ और उपवास के जरिए आत्मशुद्धि और आत्ममंथन पर जोर देते हैं। 'उत्तम क्षमा' पर लोगों से अपने जाने-अनजाने में हुए गलत व्यवहार के लिए माफी मांगना और दूसरों को माफ करना इस परंपरा का अहम हिस्सा है।

अंकिता ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी मंदिर यात्रा की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें वह पति विक्की के साथ नजर आईं। इस दौरान वह नारंगी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखाई दी। इस खास मौके पर उन्होंने सभी लोगों से माफी मांगी।तस्वीरें शेयर करते हुए अंकिता ने कैप्शन में लिखा, "साफ दिल के साथ हम उन सभी से माफी मांगते हैं, जिन्हें जाने-अनजाने हमारी वजह से किसी भी तरह की ठेस पहुंची हो। उत्तम क्षमा।"

अंकिता के इस पोस्ट पर एक्टर अर्जुन बिजलानी ने मजेदार अंदाज में कमेंट किया। उन्होंने लिखा, "चल माफ किया," और साथ में लाफ्टर इमोजी का भी इस्तेमाल किया।

गौरतलब है कि अंकिता लोखंडे और विक्की जैन इससे पहले भी अलग-अलग त्योहारों को पूरे उत्साह के साथ सेलिब्रेट करते नजर आए हैं। हाल ही में अंकिता ने अपने घर पर परिवार और दोस्तों के साथ गौरी-गणपति फेस्टिवल का ग्रैंड सेलिब्रेशन किया था। इस मौके पर उनके करीबी दोस्त और टीवी प्रोड्यूसर एकता कपूर भी उनके घर पहुंची थीं।

सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में अंकिता एकता कपूर को गौरी स्थापना की परंपरा और इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में बताती दिखाई दीं। उन्होंने एकता को बताया कि महाराष्ट्र के घरों में गौरी मां के आगमन को बेहद खास माना जाता है। इस परंपरा के अनुसार गौरी मां अपने मायके आती हैं और कुछ समय वहां रहने के बाद अपने पुत्र भगवान गणेश के साथ वापस लौटती हैं। उनके वापस जाने को गौरी-गणपति विसर्जन के तौर पर मनाया जाता है।

विदेश

डीआरसी में पलटी नाव, 12 लोगों की मौत और कई लापता

किंशासा। पूर्वी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो (डीआरसी) में किवु झील में एक नाव के पलटने से 12 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लापता हैं। दुर्घटना शनिवार रात और रविवार सुबह के बीच हुई। नाव साउथ किवु प्रांत की राजधानी बुकावु से निकली थी और यात्रा के दौरान पलट गई।

नेपाल में हिमस्खलन: हिमलुंग बेस कैंप से कई लोग लापता

काठमांडू। नेपाल के मनांग जिले में माउंट हिमलुंग बेस कैंप पर रविवार को आए बर्फीले तूफान (हिमस्खलन) के बाद कई नेपाली एक्सपीडिशन गाइड और कर्मचारी लापता हैं। अभियान से जुड़ी कंपनियों ने यह जानकारी दी है। चढ़ाई शुरू करने से पहले ये लोग बेस कैंप में रस्सियां लगाने और टेंट लगाने के लिए मौजूद थे।

ट्रंप की 'न' के बाद होर्मुज को लेकर अपनी शर्तों पर अड़ा ईरान

तेहरान। ईरान ने होर्मुज होर्मुज को फिर से खोलने की अपनी शर्तों में किसी तरह का बदलाव न करने का फैसला किया है। विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार को इसे लेकर बयान दिया।

ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को ठुकराने के बाद अपना रुख स्पष्ट किया।स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा जलमार्ग है जो दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति के लिए बहुत अहम है। यही अब वाशिंगटन और तेहरान के बीच चल रहे टकराव का केंद्र बन गया है। यह टकराव लगभग सात महीने पहले ईरान पर अमेरिका-इजरायल के संयुक्त हमलों के बाद शुरू हुआ था। विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अनुसार, ईरान की योजना में मध्य-पूर्व (लेबनान सहित) में सभी तरह की शत्रुता को खत्म करना और उस युद्धविराम समझौते की शर्तों को पूरा करना शामिल था जो महीनों पहले टूट गया था।

होर्मुज को लेकर हुई लड़ाई के दौरान टूटे उस समझौते में ईरान की फ्रीज की गई संपत्ति को जारी करने, ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों को हटाने और अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को खत्म करने की बात कही गई थी। ईरान के सरकारी प्रसारक आईआरआईबी की रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने रविवार को कहा, 'हमारी शर्तें स्पष्ट हैं, और होर्मुज को फिर से खोलने की दिशा में कोई भी कदम इन शर्तों के पूरा होने पर ही निर्भर करेगा। हम इनसे पीछे नहीं हटेंगे।'

उन्होंने कहा, 'हमने कूटनीति या संवाद के दरवाजे कभी बंद नहीं किए, लेकिन साथ ही, हम अपने अधिकारों से कभी पीछे नहीं हटे हैं।'ट्रंप ने शनिवार को कहा था कि उन्होंने युद्धविराम समझौते को ठुकरा दिया। पत्रकारों से बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, 'वे एक ऐसा समझौता करना चाहते हैं जिसमें वे तुरंत स्ट्रेट को खोल दें क्योंकि उन्हें बहुत बुरी तरह हार का सामना करना पड़ रहा है। वे समझौता करना चाहते हैं और मुझे लगता है कि यह ठीक है। मुझे भी समझौता करना पसंद है।'

अराघची ने रविवार को कहा कि ईरानियों ने 'अमेरिकी राष्ट्रपति की पहली प्रतिक्रिया देखी, लेकिन अब तक मध्यस्थों की ओर से हमें कुछ भी नहीं बताया गया है।' वाशिंगटन और तेहरान ने जून में पाकिस्तान की मध्यस्थता में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए थे, जिसका उद्देश्य युद्ध को खत्म करना, होर्मुज को फिर से खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करना था।लेकिन कुछ समय बाद ही यह समझौता टूट गया जब ईरान ने होर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी की। ईरान का आरोप था कि ये जहाज जलडमरूमध्य से गुजरने के लिए तय रास्ते से भटक गए थे।

दक्षिण अफ्रीका में सड़क हादसा: ट्रक से टकराई मिनीबस, 11 की मौत और 8 घायल

जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका के क्वाज़ुलु-नताल प्रांत में रविवार को सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई जबकि 8 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मिनीबस और ट्रक की ये आमने-सामने की भिड़ंत थी। 'इंडिपेंडेंट ऑनलाइन' ने प्रांत के ट्रांसपोर्ट और ह्यूमन सेटलमेंट्स विभाग के हवाले से बताया कि यह हादसा स्थानीय समयानुसार सुबह करीब 4 बजे (0200 जीएमटी) इनकोसी म्तुबातुबा म्युनिसिपैलिटी में एन2 हाईवे पर हुआ।उत्तर की ओर जा रही एक मिनीबस टैक्सी विपरीत दिशा यानी दक्षिण की ओर आ रहे ट्रक से टकरा गई। धमाके सी आवाज सुनाई दी और इसके ही साथ वाहन में आग लग गई। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

दक्षिण अफ्रीका में 24 घंटों के भीतर दो जगहों पर बरसाई गईं गोलियां, 27 की मौत

प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका में वीकेंड पर गोलीबारी की दो अलग-अलग वारदातों में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए।

दक्षिण अफ्रीका के अखबार 'द सिटिजन' की रिपोर्ट के मुताबिक, लवांडले में पार्टी स्थल पर हुई गोलीबारी की घटना में 10 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए।दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेवा (एसएपीएस) ने बताया कि रविवार को तड़के 2 बजे (स्थानीय समय) तड़के लवांडले में हथियारबंद लोगों ने पार्टी कर रहे लोगों पर गोलीबारी की। पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच अन्य की अस्पताल ले जाने के बाद मौत हो गई।कुल 11 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। लवांडले पुलिस ने संदिग्धों के खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है।

बीएलएफ का दावा, 'समूह की महिला यूनिट ने पाकिस्तान के नौ सुरक्षाकर्मियों को किया ढेर'

क्वेटा। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) ने दावा किया है कि समूह के नए महिला दस्ते 'करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन' (केएडी) के हालिया हमलों में पाकिस्तानी सैन्य बलों के नौ जवान मारे गए।

बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक, बीएलएफ प्रवक्ता मेजर ग्वाहराम बलूच ने एक बयान में कहा कि 22 सितंबर को तुरबत के पास जुशाक इलाके में चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) राजमार्ग पर तीन वाहनों वाले क्विक रिस्पॉन्स फोर्स (क्यूआरएफ) के काफिले पर केएडी ने हमला किया। समूह का दावा है कि हमले में छह सैन्यकर्मी मारे गए और कई अन्य घायल हुए। प्रवक्ता के अनुसार, बीएलएफ की कुर्बान यूनिट ने भी इस अभियान में केएडी का साथ दिया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी बलों ने दोनों दस्तों को घेरने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुकाबला करते हुए सुरक्षित वापसी की।

हमले में कई सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचने का भी दावा किया गया। इस दौरान कुर्बान इकाई का एक लड़ाका चाकर मुराद उर्फ दिलीप जान भी मारा गया।ग्वाहराम बलूच ने दावा किया कि केएडी ने बलूचिस्तान के कलात जिले की मंगुचर तहसील में क्वेटा-कराची राजमार्ग पर तीन स्थानों पर नाकेबंदी की। मंगुचर बाजार की ओर से बख्तरबंद वाहन और दो अन्य वाहनों में पहुंचे पाकिस्तानी बलों पर हमला किया गया, जिसमें दो सैन्यकर्मी मारे गए। समूह ने दावा किया कि इस दौरान कई सैन्य वाहनों को नुकसान पहुंचा। बयान के मुताबिक, पाकिस्तानी बलों ने लड़ाकों को घेरने का प्रयास किया, जिसके बाद एक और मुठभेड़ हुई।

इसमें एक पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी के मारे जाने और कई अन्य के घायल होने का दावा किया गया।एक अन्य घटना में बलूच रिपब्लिकन आर्मी (बीआरए) ने बलूचिस्तान के डेरा बुगती जिले के बेह लोटी इलाके में मारी एनर्जी लिमिटेड के एक ठिकाने पर हमले की जिम्मेदारी ली। समूह के प्रवक्ता सरबाज बलूच के हवाले से बलूचिस्तान पोस्ट ने बताया कि रॉकेट और भारी हथियारों से किए गए इस हमले में कंपनी के तीन कर्मचारियों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए।सरबाज बलूच ने दावा किया कि हमले के बाद पाकिस्तानी बलों और समूह द्वारा स्थानीय स्तर पर सरकार समर्थित सशस्त्र संगठन बताए गए एक समूह के सदस्यों के बीच संघर्ष हुआ।